सत्यमेव जयते
भारत सरकार

मोदी 2.0 का एक वर्ष

आत्मनिर्भर भारत की ओर

प्रस्तावना

देश और विश्व 2020 की शुरुआत से ही कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है। सारी दुनिया के लोग लॉकडाउन में हैं और लोग इस बीमारी से लड़ने और इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के उपाय खोजने के लिए संघर्षरत हैं।

दो गज की दूरी और जीवन शैली में बदलाव एक नए रुप में सामने आया है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पहला ऐसा देश है , जिसने ठोस और व्यापक रणनीति के साथ वायरस के प्रसार को रोका और कोविड-19 के संक्रमण की संख्या को कम किया।

डब्ल्यू एच ओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत सरकार के वैश्विक महामारी से लड़ने के प्रयास की प्रशंसा की है।

भारत उन गिने-चुने देशों में से एक है जिसने कोविड-19 के 500 से भी कम मामलों के पहले ही संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नागरिकों ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने में अपनी पूरी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया।

भारत ने इस संकट को एक अवसर में बदलने की पूरी कोशिश की जिससे ये आत्मनिर्भरता के माध्यम के रूप में उभरा, और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाए गये।

जब कोरोना संकट शुरु हुआ था, तब भारत में एक भी पी पी ई किट नहीं बनाई जाती थी। भारत में एन-95 मास्क भी बहुत कम मात्रा में तैयार किए जाते थे।

आज हम प्रतिदिन 2 लाख पी पी ई किट तथा 2 लाख एन-95 मास्क तैयार करने की स्थिति में हैं। हम ऐसा करने में सफल रहे क्योंकि भारत ने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया।

भारत का दृष्टिकोण - संकट को अवसर में बदलना - हमारे संकल्प स्वावलंबी भारत के लिए कारगर साबित होंगे।

इस दिशा में प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और विकास को बनाए रखने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है।

प्रस्तावना

मोदी सरकार 2.0 के पहले वर्ष में ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण सुधार पहले ही लागू किए जा चुके हैं। भारत को विश्व की एक सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाने में कार्पोरेट करों में भारी कटौती, बड़ी विनिवेश घोषणाएं, श्रम कोड सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन तथा दिवाला एवं दिवालियापन संहिता की निरंतर सफलता जैसे महत्वपूर्ण सुधार सरकार द्वारा मई, 2019 अब तक किए जा चुके हैं।

अप्रैल-मई 2019 में आम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में भारी बहुमत से वापसी हुई।

सरकार ने ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए जिससे भारत का कायापलट हुआ और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इनमें सबसे पहले अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त कर देश की दशकों पुरानी मांग को पूरा किया गया।

अयोध्या राम जन्मभूमि से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद स्थिति को संभालने के दौरान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनकी दूरदर्शिता एक बार फिर साबित हुई।

सदियों पुराने रोहिंग्या शरणार्थी विद्रोह की समाप्ति तथा पूर्व कार्यकर्ताओं को मुख्यधारा में शामिल कर त्रिपुरा में शामिल किया जाना और बोडो समझौता, प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' दृष्टिकोण की एक विलक्षण पहचान है।

कई अन्य वादे जैसे की पीएम-किसान योजना का लाभ सभी किसानों को देने, छोटे व्यापारियों और किसानों को पेंशन देने, एक एकीकृत जल शक्ति मंत्रालय का गठन करने और बहुत कुछ पहले ही पूरे किए जा चुके हैं।

निम्नलिखित पृष्ठ पिछले एक साल में मोदी 2.0 सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों, भारत के इतिहास में एक निर्णायक अवधि और एक नए भारत, एक उज्ज्वल भारत की शुरुआत का संक्षिप्त विवरण देते हैः-

कोविड-19 के विरुद्ध

भारत की लड़ाई में शीर्ष पर प्रधानमंत्री

- कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने और कोविड-19 से लड़ने के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न हितधारकों के साथ प्रतिदिन बैठकें की
- मंत्रियों के साथ बातचीत की और लगातार उनसे कोरोना वायरस से संबंधित मुद्दों पर नियमित फीडबैक लिए

https://pib.gov.in/PhotoCategories.aspx?MenuId=8

- कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव से नियमित तौर पर ब्रीफिंग ली।
- वित्तीय, कृषि, शिक्षा, नागरिक उड्डयन, विद्युत क्षेत्रों की समीक्षा के लिए बैठकें की।
- प्रतिदिन 150 से अधिक लोगों के साथ बातचीत की।
- नियमित रूप से फोन के जरिये और व्यक्तिगत रूप से डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों, सफाईकर्मियों, कोविड रोगियों और इस बीमारी से ठीक हुए लोगों से बातचीत की।
- प्रिंट मीडिया, टीवी चैनलों, रेडियो जॉकी, धार्मिक नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों / सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की।
- प्रधानमंत्री ने अलग से विदेशों के विभिन्न प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की।
- डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किए
- फार्मा सेक्टर और आयुष चिकित्सकों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की ।

राज्यों के साथ मिलकर काम किया

20 मार्च से 11 मई के बीच प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के प्रयास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 5 बार बातचीत की।

उदाहरण के तौर पर आगे रहे

प्रधानमंत्री ने घोषणा करके लोगों द्वारा दो गज की दूरी बनाए रखने के प्रयास की भावना के चलते होली उत्सव में भाग नहीं लिया।

राष्ट्र के नाम संबोधन

श्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च के बाद से पांच बार राष्ट्र को संबोधित किया और लोगों को लॉकडाउन का पालन करने और दो गज की दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

https://www.youtube.com/watch?v=P4QjOhu9eIQ

दो गज की दूरी

देश भर में ग्राम पंचों के साथ अपनी बातचीत में, प्रधानमंत्री ने नागरिकों से लोगों के बीच दो गज की दूरी बनाए रखने के लिए कहा।

https://www.youtube.com/watch?v=GVgj9MQkS-0

"आत्मनिर्भर और स्वावलंबी ये दोनों बड़े सबक कोरोना महामारी से सीखे गए- पीएम

कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्य बल

महामारी के कारण होने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए, प्रधानमंत्री ने केंद्रीय वित्तमंत्री की देखरेख में कोविड -19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्य बल 'बनाने की घोषणा की।

1.7 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की

नरेंद्र मोदी सरकार ने 26 मार्च को 1.7 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की घोषणा की, जो गरीबों को दी जाने वाली आपातकालीन नकद हस्तांतरण पर केंद्रित है।

संकट की घड़ी में पड़ोसियों को साथ लाना

प्रधानमंत्री ने सार्क पड़ोसियों का नेतृत्व किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोविड -19 के खिलाफ क्षेत्रों की लड़ाई को कारगर बनाया

https://www.youtube.com/watch?v=tkQQYFQP9zM

असाधारण अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री ने 26 मार्च को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जी -20 के नेताओं के साथ बातचीत की

प्रधानमंत्री ने 4 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से NAM संपर्क समूह के साथ भी बातचीत की

https://www.youtube.com/watch?v=VtR1CWjDXYs

प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ बातचीत

प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, खाड़ी और पश्चिम एशिया के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों के साथ फोन पर बात की।

पीएम गरीब कल्याण योजना

- पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना वायरस से प्रभावित गरीबों की मदद के लिये 26 मार्च 2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपए का राहत कोष घोषित।
- कोविड 19 से लड़ रहे हर चिकित्सा कर्मी को 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा।
- 80 करोड़ गरीब परिवारों को अगले तीन महीने तक हर माह 5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो पसंद की दाल मुफ्त दी जाएगी।
- जन धन खाता धारक 20 करोड़ महिलाओं को अगले तीन महीने तक प्रतिमाह 500 रुपए दिए जाएंगे।
- 8 करोड़ गरीब परिवारों को 1 अप्रैल 2020 से अगले तीन महीने तक मुफ्त एलपीजी सिलिंडर।
- मनरेगा मजदूरी को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन किया गया। इससे 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।
- 3 करोड़ गरीब वृद्ध जनों, गरीब दिव्यांगजनों और गरीब विधवाओं को 1000 रुपए की एक्सग्रेसिया राशि।
- पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में 9.72 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए दिये गए।
- भवन और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों राहत पहुंचाने के लिये केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।
- सरकार ने 100 से कम श्रमिकों वाले व्यवसायों में प्रति माह 15,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले मजदूरों के पीएफ खाते में अगले तीन महीनों के लिए मासिक मजदूरी का 24 प्रतिशत भुगतान करने का निर्णय लिया।
- 3 करोड़ वृद्ध विधवाओं और दिव्यांगजनों को राहत देने के लिए अगले तीन माह में 1,000 रु प्रति व्यक्ति दिये जाएंगे।
- 63 लाख स्वयं सहायता समूहों(एसएचजी) के माध्यम से महिलाओं के लिए संपार्श्विक मुक्त उधार की सीमा 10 रुपये से बढ़ाकर 20 लाख की गई।
- संगठित क्षेत्र - कर्मचारी भविष्य निधि रेगुलेशन में संशोधन करके इसमें महामारी को शामिल किया गया जिसके तहत अब फंड की 75 प्रतिशत गैर-वापसी योग्य राशि या तीन महीने की मजदूरी की अग्रिम राशि में से जो भी कम हो, उनके खातों से निकाली जा सकेगी।
- राज्य सरकारों को जिला खनिज निधि (DMF) के तहत उपलब्ध फंड का उपयोग मेडिकल जांच, स्क्रीनिंग और अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिये करने को कहा जाएगा जिससे कोविड 19 के फैलाव को रोका जा सके और रोगियों का बेहतर उपचार किया जा सके।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिये 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की।

https://www.youtube.com/watch?v=aIXSG9d-0rU

आत्मनिर्भर भारत अभियान

एक आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने आहवाहन में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकास को बनाए रखने के लिए पांच स्तंभों पर जोर दिया: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, प्रणाली (आधुनिक तकनीक पर आधारित), वाइब्रेन्ट जनसांख्यिकी और मांग।

प्रधानमंत्री ने भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर केन्द्रित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की

https://www.youtube.com/watch?v=aIXSG9d-0rU

गरीबों के लिए राहत, प्रवासियों और व्यथित लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान, सस्ता ऋण, किफायती आवास

प्रवासी

3500 करोड़ मुफ्त खाद्यान्न- 8 करोड़ प्रवासियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं/चावल और प्रति परिवार 1 किलो दाल

सड़क विक्रेता

सड़क विक्रेताओं के लिए 5000 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सुविधा- 5 लाख सड़क विक्रेताओं को लाभ।

रोजगार सृजन

- **रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के बजट मे 1,01,500 करोड़ की वृद्धि।**
  - कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ व्यक्ति दिवस के बराबर रोजगार का सृजन होगा।
  - लौट रहे प्रवासी मजदूरों की अधिक रोजगार की मांग को पूरा करेगा।
  - जल संरक्षण परिसंपत्तियों सहित टिकाऊ और आजीविका संबंधी परिसंपत्तियों के बड़ी संख्या में सृजन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।

मुद्रा ऋण

- शिशु मुद्रा ऋण के लिए 1500 करोड़ रुपए की मुद्रा ऋण राहत।
- 12 माह की अवधि के लिए ब्याज दर में 2% की कटौती।

शहरी आवास

- 6 से 18 लाख रुपए सालाना आय वालों के लिए 70,000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता योजना।
- किफायती आवास - प्रवासी मजदूरों और गरीब शहरी लोगों के लिए योजना।

  - किफायती किराए के आवास परिसर - शहरों में सरकारी निधि से बने घरों को किफायती किराए के आवासीय परिसरों में परिवर्तित करना (सीएआरएचसी) भूमि पर एआरएचसी विकसित करने के लिए उद्योगों, राज्य और केंद्रीय सरकार की एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

किसानों की मूल्य निर्धारण की शक्तियों में वृद्धि, ऐतिहासिक बाधाओं को दूर करना।

अनिवार्य वस्तु अधिनियम में संशोधन

- किसानों को बेहतर मूल्य निर्धारण उपलब्ध करवाएगा।
- यह अनाज सहित खाद्य पदार्थों को अनियमित करेगा जो उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और निवेश को आकर्षित करने में मदद करते हैं।

किसान

- किसान ऋण कार्ड के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती ऋण- 2.5 करोड़ किसान और मछुआरों के लिए ।
- 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी निधि- नाबार्ड – 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ।

कृषि अवसंरचना निधि

- 1 लाख करोड़ रुपए – कृषि इन्फ्रा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सुविधा

मत्स्य

- 20,050 करोड़ रुपए – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए।
- समुद्री गतिविधियों, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलचर के लिए 11,000 करोड़ रुपए ।
- मछली पकड़ने के बंदरगाहों, कोल्ड चेन, बाजारों आदि को 9000 करोड़ रुपए।

पशुपालन - 15,000 करोड़ रुपए के जरिये – डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और पशु आहार अवसंरचना में निजी निवेश करना ।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम – 13,343 करोड़ रुपए पशुओं के पैर और मुँह की बीमारी और ब्रूसीलोसिस के टीकाकरण हेतु

जड़ी-बूटी की खेती को बढ़ावा देना - 4000 करोड़ रुपए का परिव्यय – दो साल में 10,00,000 हेक्टेयर कवर किया जाना है।

मधुमक्खी पालन – मूल संरचना को विकसित करने के लिए 500 करोड़ – 2 लाख किसानों को लाभ

ऑपरेशन ग्रीन- 500 करोड़ रुपए की इस सहायता को टमाटर, प्याज, आलू से बढ़ाकर सभी सब्जियों और फलों के लिए प्रयोग किया जाना ।

सूक्ष्म खाद्य उद्यम – 10 हजार करोड़ रुपए – 2 लाख सूक्ष्म खाद्य उद्यम के लिए खाद्य मानकों को प्राप्त करने, ब्रांड बनाने और, विपणन के लिए तकनीकी उन्नयन की जरूरत को पूरा करने हेतु

छोटे उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए **5.94 लाख करोड़** की सहायता ।

एमएसएमई

- एमएसएमई की परिभाषा को विस्तृत किया गया
- 3 लाख करोड़ रुपए के संपाश्विक मुक्त स्वचालित ऋण
- कमज़ोर एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए का मातहत ऋण।
- निधियों की निधि के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूज़न

एनबीएफसी

- एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई को 30,000 करोड़ रुपए की सहायता।
- केवल एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ रुपए की सहायता।

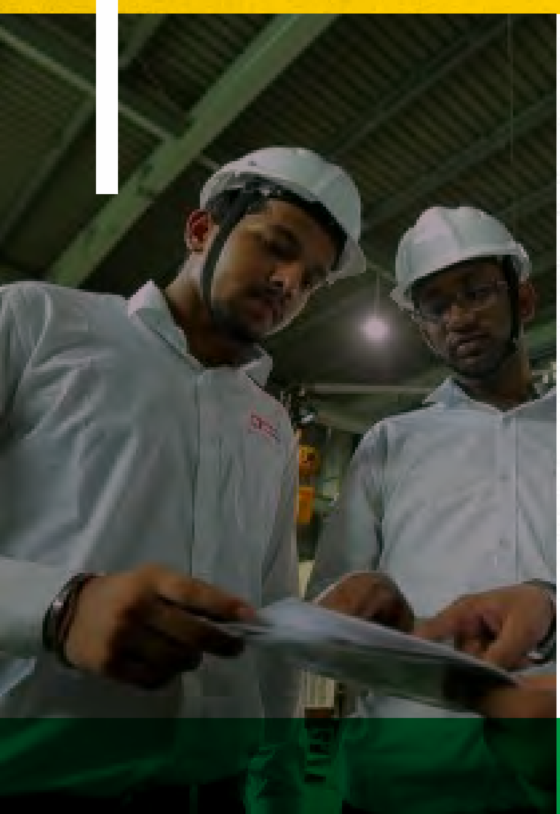

ईपीएफ

- व्यापार और कर्मचारियों के लिए 3 माह हेतु 6750 करोड़ रुपए के ईपीएफ योगदान में कमी ।
- व्यापार और कर्मचारियों के लिए 3 माह हेतु 2500 करोड़ रुपए की ईपीएफ सहायता ।

पॉवर डिस्कॉम – 90,000 करोड़ रुपए की सहायता

- बिजली वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सहायता हेतु डिस्कॉम को दो समान किस्तों में 90,000 करोड़ रुपए की सहायता ।

200 करोड़ रुपए तक की निविदाएं अब वैश्विक नहीं

विभिन्न क्षेत्रों का खुलना

एफडीआई में वृद्धि -
लालफीताशाही को कम किया गया

रक्षा:

- रक्षा उत्पाद में एफडीआई में 49% से 74% की वृद्धि
- हथियारों/प्रणालियों की सूची जिनके आयात पर प्रतिबंध होगा।
- आयातित हिस्से पूर्जों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना।
- आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमन

नागर विमानन

- भारतीय एयर स्पेस के प्रतिबंधों मे कमी कर यात्री विमान की क्षमता बढ़ाने, ईंधन बचाने और विश्व स्तरीय हवाई अड्डों के लिए प्रयास।
- पीपीपी रुट के माध्यम से और अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे: दूसरे चरण की बोली के लिए 6 और हवाई अड्डों की पहचान की गई।
- पहले और दूसरे चरण में 12 हवाई अड्डों के लिए निजी निवेशकों द्वारा अतिरिक्त निवेश जिससे 13,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है।
- तीसरे चरण की बोली के लिए 6 अन्य को अधिसूचित किया गया
- वायुयानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाना।

ऊर्जा क्षेत्र

- उपभोक्ता अधिकारों, उद्योग को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र की सततता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र की ऊर्जा नीति में सुधार।
- संघ राज्य क्षेत्र के ऊर्जा विभाग/संघ राज्य क्षेत्रों में उपयोगिताओं के वितरण का निजीकरण किया जाएगा।

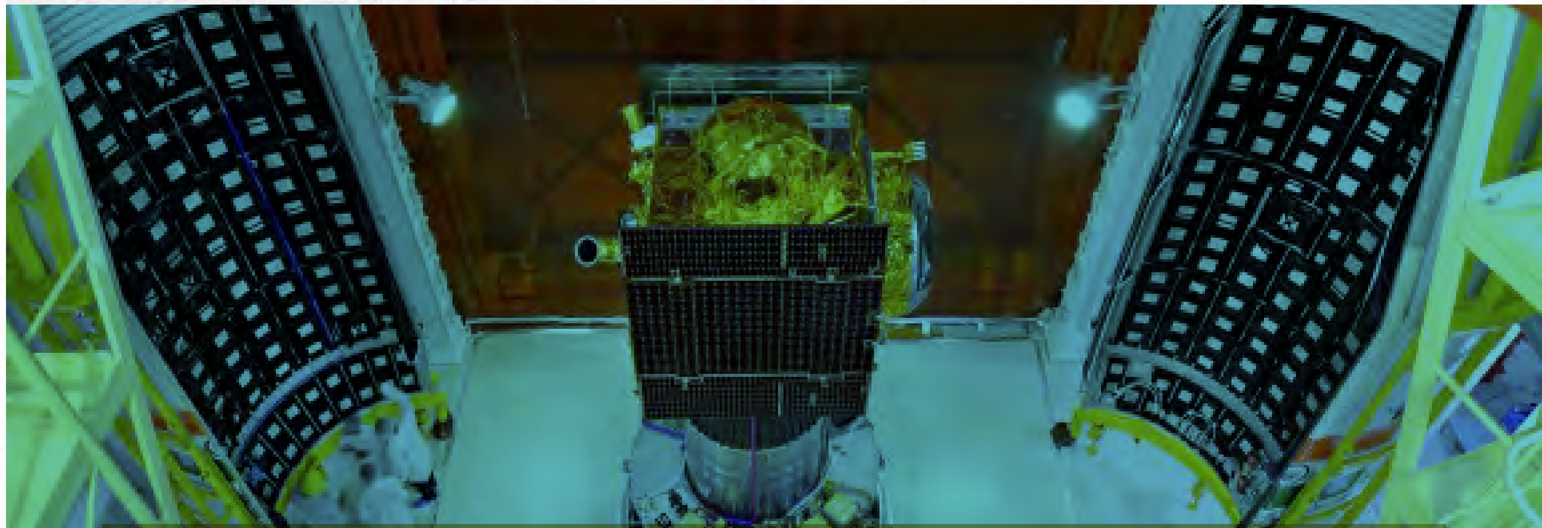

अंतरिक्ष क्षेत्र

- सेटेलाइट प्रक्षेपण और अन्य अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी संस्थानों को अनुमति।
- निजी क्षेत्र को उनकी क्षमता में सुधार के लिये इसरो की सुविधाओं और अन्य संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति।
- ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष यात्रा आदि भविष्य की परियोजनाओं में भी निजी क्षेत्र को अनुमति।

सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर

- सामाजिक अवसंरचना में निवेश करने वाली निजी परियोजनाओं के लिए 8100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सरकार की 'व्यवहार्यता गैप फंडिंग' मौजूदा 20% से बढ़ाकर 30% की गई।

कोयला - कोयले के आयात को कम करने और आत्म निर्भरता को बढ़ाने की आवश्यकता

- कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की शुरुआत।
- निश्चित रुपए या टन की नीति की बजाए राजस्व साझाकरण तंत्र।
- कोई भी समूह कोयला ब्लॉक के लिए बोली लगा सकता है और खुले बाजार में बेच सकता है।
- प्रवेश मानदंडों को उदार बनाया जाएगा और लगभग 50 ब्लॉकों को तुरंत खोला जाएगा।
- राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण/ द्रवीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन।

खनन

- खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा।
- एक निर्बाध एवं समग्र अन्वेषण-सह-खनन-सह-उत्पादन व्यवस्था को प्रोत्साहन।
- 500 खनन ब्लॉकों को एक खुली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से खोला जाएगा।
- एल्यूमिनियम उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की संयुक्त नीलामी।
- बंदी और गैर-बंदी खानों के बीच के अंतर को खत्म किया जाएगा।

स्वास्थ्य देखभाल का विकास

- प्रधानमंत्री द्वारा 15,000 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य पैकेज का ऐलान।
    - हेल्थकेयर के लिए 15,000 करोड़ रुपये का इमरजेंसी वित्तीय पैकेज – इसका उपयोग चिकित्सा पेशेवरों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ज्यादा आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू बेड, और चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए होगा।
- 800 से अधिक कोविड हॉस्पिटल्स का निर्माण।
- लैब्स में 1 से लेकर 300 से अधिक की बढ़ोतरी।
- पीपीई और मास्क का निर्माण शून्य से बढ़कर 4 लाख तक हुआ।
- फेस मास्क(2 प्लाई 3 पलाई सर्जिकल मास्क, N95 मास्क) और हैंड सेनिटाइज़र को 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए आवश्यक वस्तु घोषित किया गया।
- हैंड सैनिटाइज़र के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त अल्कोहल की कीमतें दिनांक 05.03.2020 की प्रचलित कीमत से अधिक नहीं होंगीं।
- तीन लेयर वाले सर्जिकल मास्क की अधिकतम कीमत 16 रुपए प्रति नग से अधिक नहीं होगी।

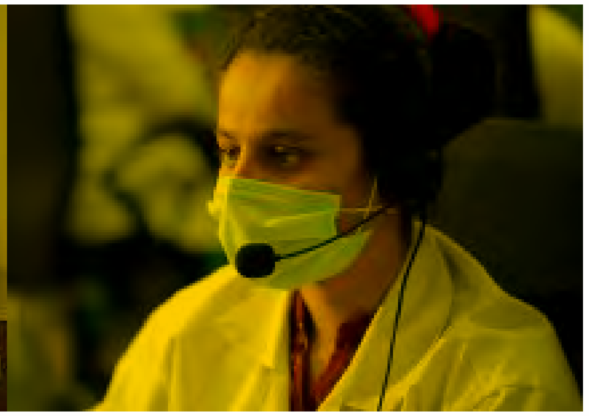

राज्य सरकारों को वित्त पोषण

- कोविड 19 संकट के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए कुल 17,287.08 करोड़ जारी किए गए।
- 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत इसमें 14 राज्यों - आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल - 'राजस्व घाटा अनुदान' के तहत 6,195.08 करोड़ रुपए।
- शेष 11,092 करोड़ रुपए सभी राज्यों को केंद्रीय हिस्से के एसडीआरएफ की पहली किस्त के अग्रिम भुगतान के रूप में दिए जाएंगे।

बजटीय सहायता और रिफंड

- "स्पेशल रिफंड और ड्राबैक डिस्पोजल ड्राइव" - व्यावसायिक संस्थाओं, विशेष रुप से एमएसएमई की मदद करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर 18,000 करोड़ रुपये के रिफंड दिये गए।
- प्रत्यक्ष कर - 5 लाख तक के सभी लंबित आयकर रिफंड को तुरंत जारी कर लगभग 14 लाख करदाताओं को लाभ पहुंचाया गया।
- सीमा शुल्क - वेंटिलेटर, फेस मास्क, सर्जिकल मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) कोविड -19 परीक्षण किट के निर्माण के लिए आयात पर बेसिक सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट दी गई।

कोविड-19 से संबंधित आयातों की सीमा-शुल्क में छूट

निम्नलिखित वस्तुओं के आयात पर तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर, 2020 तक मूल सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में दी गई छूट-

- वेंटिलेटर,
- फेस मास्क, सर्जिकल मास्क,
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)
- कोविड-19 परीक्षण किट
- उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए इनपुट

कोविड-19 के दौरान एमएसएमई और अन्य कंपनियों को सुविधा देना

- कोविड 19 की वजह से उभरते वित्तीय संकट के कारण, सरकार ने भारतीय दीवालिया कानून(आईबीसी) 2016 के तहत डिफ़ॉल्ट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है। यह एमएसएमई के मामलों में इनसॉल्वेंसी की कार्यवाही को गति देगा।
- अस्थायी/आकस्मिक/ दैनिक वेतन श्रमिकों को एक्सग्रेशिया भुगतान करने के लिये कारपोरेट सोशल दायित्व फंड के उपयोग की अनुमति।
- वीसी या ओएवीएम के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठकें (ईजीएम) रखने की अनुमति वाली कंपनियों ने ई-वोटिंग सुविधा के साथ पूरक/ पंजीकृत ईमेल के माध्यम से मतदान को सरल बनाया, ताकि शेयरधारकों को शारीरिक रुप से इकट्ठा होने की आवश्यकता न हो।

अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान की गई

- भारत ने अमेरिका और ब्राज़ील को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात की अनुमति दी जहां कोविड-19 के हजारों मामले सामने आए हैं।
- भारत द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पेरासिटामोल और अन्य सामग्री इज़राइल, अफ़ग़ानिस्तान शार्क देशों और अफ्रीकन नेशन को भेजे गए।

प्रवासियों को घर भेजना

श्रमिक एक्सप्रेस

- रेलवे ने लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए "श्रम दिवस" 1 मई 2020 से "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों की शुरुआत की।
- अब तक 45 लाख से अधिक यात्री अपने गृह राज्य पहुंचाए जा चुके हैं।
- संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए देश भर में 3270 ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
- प्रवासियों को 74 लाख से अधिक मुफ्त भोजन और 1 करोड़ से अधिक पानी की बोतलें प्रदान की गईं।

विदेशों में फंसे हुए भारतीयों की वापसी

- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने विदेश में फंसे 40,000 से अधिक भारतीयों को वापस देश में लाने का काम किया है।
- फरवरी से अप्रैल 2020 तक 48 विदेशियों सहित लगभग 2500 भारतीयों को गंभीर रुप से प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया।
- भारत के 72 शहरों से 58,000 से अधिक विदेशी नागरिकों को भारत सरकार द्वारा उनके देश वापस भेजने की सुविधा प्रदान की गई है।
- 7 मई 2020 से भारत ने दुनिया भर में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन आरंभ किया।
- 193 हवाई उड़ानों और 3 नौसेना के जहाजों द्वारा 27 मई 2020 तक 37,340 से अधिक लोगों को स्वदेश वापस लाया गया।

लाइफलाइन उड़ान मिशन

कोविड -19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के क्रम में देश के दूरदराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा कार्गो के परिवहन के लिए 26 मार्च 2020 से 'लाइफलाइन उड़ान' संचालित की जा रही हैं।

- 23 मई, 2020 तक एयर इंडिया, एलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और निजी वाहकों द्वारा 'लाइफलाइन उड़ान' के तहत 571 उड़ानें संचालित की गईं। इनमें से 315 उड़ानें एयर इंडिया और एलायंस एयर द्वारा संचालित की गई हैं ।
- इन उड़ानों के माध्यम से लगभग 916.49 टन चिकित्सा सामान का परिवहन किया गया है।
- इसमें देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र, द्वीप क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

कोविड राहत कार्यों में सशस्त्र बलों की प्रमुख भूमिका

- सशस्त्र बलों ने कोविड-19 प्रभावित देशों जैसे चीन, ईरान, इटली, मलेशिया आदि में फंसे भारतीयों को राहत सामग्री प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।
- सशस्त्र बलों ने अपने मेडिकल और अन्य स्टाफ को तैनात कर देश भर में राहत सामग्री पहुंचाई है।
- कोविड-19 के मरीजों के इलाज और उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए सशस्त्र बलों के अस्पताल और चिकित्सा सुविधाओं आदि का उपयोग किया जा रहा है।

ऑपरेशन समुद्र सेतु

- भारतीय नौसैनिक जहाज जलाश्व और मगर द्वारा मालदीव से कुल 1488 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक वापस लाया गया।
- भारतीय नौसेना के जहाज केसरी ने मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस में खाद्य पदार्थ, कोविड संबंधित दवाएं एचसीक्यू की गोलियां सहित विशेष आयुर्वेदिक दवाएं और चिकित्सा सहायता टीमों की सेवाएं प्रदान कीं।

कोविड -19 से लड़ने के लिए हैंड-सैनिटाइज़र का उत्पादन

- श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगभग 165 डिस्टिलरी और 962 स्वतंत्र निर्माताओं को देश भर में हैंड-सैनिटाइज़र बनाने के लिए लाइसेंस दिए गए, जिसके परिणामस्वरुप 11.05.2020 तक 87,20,262 लीटर हैंड-सैनिटाइज़र का उत्पादन हुआ है।

पीपीई का उत्पादन

- भारत अब तक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) और एन -95 मास्क के आयात पर निर्भर था।
- प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया।
- भारत ने जनवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में पीपीई और एन-95 मास्क का उत्पादन शुरू किया।
- 12.05.2020 तक कुल 41.91 लाख पीपीई किट और 75.94 लाख एन-95 मास्क भारत में बनाए गए हैं। देश में पीपीई का उत्पादन 3.20 लाख प्रतिदिन होने का अनुमान है।

कोविड -19 की जाँच के लिए स्वदेशी स्वैब स्टिक्स: ए मेक इन इंडिया स्टोरी

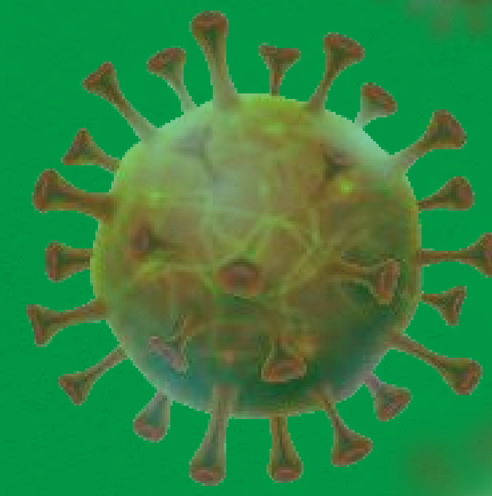

- वैश्विक आपूर्ति बाधित होने पर और देश में परीक्षण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत ने उच्च गुणवत्ता, कम लागत वाले परीक्षण स्वैब का उत्पादन करने के लिए कमर कसी जो देश के लाखों लोगों के लिए उपलब्ध हो सके।
- माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में भारत एक उच्च गुणवत्ता वाले कोविड परीक्षण स्वैब का निर्माण करने के लिए तैयार था।
- 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत अवधारणा से उत्पादन मात्र सात दिनों में डिजाइन, अधिप्रमाणन और अनुमोदन सहित सारी औपचारिकताएं गंभीर लॉकडाउन परिस्थितियों में पूरी की गईं।
- 6 मई, 2020 से स्वैब का उत्पादन शुरु हुआ।
- इससे रिकॉर्ड समय में आयातित स्वैब से बेहद आंशिक मूल्य पर लाखों उच्च गुणवत्ता वाले परीक्षण स्वैब का उत्पादन हुआ।

संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) का दो वर्षों तक गैर संचालन

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत दो साल (2020-21 और 2021-22) के लिए संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना **(एमपीएलएडीएस)** को लागू नहीं करने का फैसला किया है। इस फंड का उपयोग देश में कोविड19 की चुनौतियों और प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन में सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए किया गया।

PM CARES
Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund

पीएम केयर फंड का निर्माण

- एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट - 'प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत निधि' (पीएम केयर फंड) का गठन।
- किसी भी तरह के आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल या किसी अन्य प्रकार की मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदा में इसका उपयोग होगा।
- कोविड -19 के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये पहले से ही 3100 करोड़ रु प्रदान किये जा चुके हैं।
  - वेंटिलेटर की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपये
  - प्रवासियों के लिए 1000 करोड़ रुपये
  - टीकाकरण विकास के लिए 100 करोड़ रुपये

एक वर्ष के लिए सांसदों के पारिश्रमिक में 30% की कमी और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता जुलाई 2021 तक रोक दिये गए हैं।

नोवेल कोरोनावायरस से निपटने के उपायों के बारे में जागरूकता और प्रसार

- दूरदर्शन और आकाशवाणी और उनके प्रादेशिक चैनलों के माध्यम से टीवी, रेडियो और यूट्यूब पर वर्चुअल क्लासेस और अन्य शैक्षिक सामग्री प्रसारित कर रहे हैं।
- फेक न्यूज़ से निपटने के लिए पीआईबी फैक्ट प्रणाली की शुरुआत की गई । इस पहल ने सोशल मीडिया पर गहरा प्रभाव छोड़ा और फेक न्यूज़ को कम करने में अहम भूमिका निभाई ।
- दूरदर्शन-धारावाहिकों 'रामायण' और 'महाभारत' के पुन: प्रसारण दूरदर्शन को दर्शकों के रिकॉर्ड को तोड़ने में सहायक रहे। डीडी नेशनल और डीडी भारती तब से बड़े पैमाने पर दर्शकों का आनंद ले रहे हैं।
- डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कम्यूनिटी रेडियो के लिए 89.6 और 90.0 मेगा हर्ट्ज़ की अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी प्रदान की ।

प्रधानमंत्री - किसान

प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 9.25 करोड़ से अधिक किसान परिवार लाभान्वित हुए और अब तक लॉकडाउन अवधि के दौरान 18,517 करोड़ रुपये वितरित किए गए ।

प्रधानमंत्री – फसल बीमा योजना

लॉकडाउन अवधि के दौरान पीएम फसल बीमा योजना के तहत **6003.6 करोड़** रुपये की राशि के कुल दावे निपटाए गए।

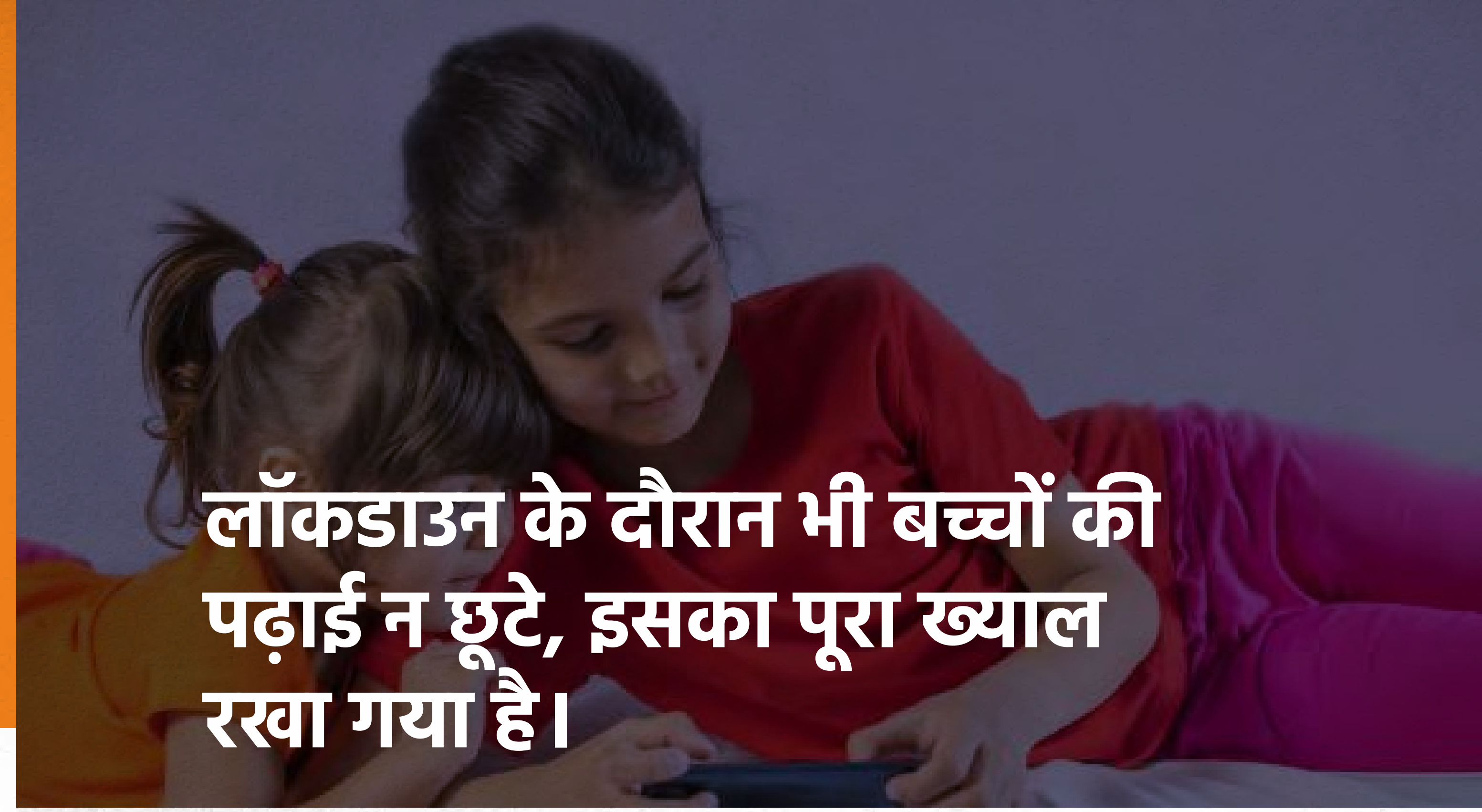

लॉकडाउन के दौरान भी बच्चों की पढ़ाई न छूटे, इसका पूरा ख्याल रखा गया है।

- प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से घर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए **वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया** और इसे जारी किया।
  - एनसीईआरटी ने स्वयं पोर्टल पर कक्षा XI & XII के छात्रों और शिक्षकों के लिए 28 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरु किए। इसमें 90,000 छात्रों ने पंजीयन कराया।
  - ई-पाठशाला के तहत 367 पाठ्यपुस्तकें तैयार की गईं।
  - ई-पाठशाला पर लगभग 14,442 ई- पाठ्यसामग्री मुफ्त संसाधन के रुप में उपलब्ध है।

स्वयं प्रभा टीवी चैनल्स

- 32 चैनलों का एक समूह उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समर्पित है।
- इन चैनलों की पहुंच बढ़ाने के लिए निजी डीटीएच ऑपरेटरों के साथ समझौता किया गया है ।
- एनसीईआरटी ने अप्रैल, 2020 से डीटीएच चैनल पर इंटरएक्टिव कक्षाएं संचालित की हैं जो अधिकांश वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर पर सभी स्तरों के लिए आधारित है।

छात्रों के लिए पदोन्नति नीति

- कक्षा एक से कक्षा आठवीं तक के छात्रों को अगली कक्षाओं के लिए उत्तीर्ण किया गया ।
- कक्षा IX और कक्षा XI के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में उत्तीर्ण किया जाएगा।

ऑनलाइन शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों और अकादमिक कैलेंडर/ परीक्षाओं से निपटने के लिए 3 टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

- स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 12 करोड़ से अधिक बच्चों को मिड डे मील प्रदान गया है।

- छात्र हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया जहाँ छात्रों को आवास, भोजन, ऑनलाइन कक्षाएं, उपस्थिति, परीक्षा, स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य, यातायात और यौन हिंसा से जुड़े मुद्दों पर सहायता दी जाएगी ।

नए भारत का उदय

धारा 370 निरस्त-

- धारा 370 को निष्प्रभावी करते हुए भारत के साथ जम्मू और कश्मीर का वास्तविक एकीकरण।
- कश्मीर को भारत के साथ एकजुट होने और राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने में मदद की है।
- जम्मू और कश्मीर के विकास में गति।
- क्षेत्र के युवकों के लिए अभूतपूर्व अवसर।
- क्षेत्र में निजी निवेशकों के द्वार खुले।
- आतंकवाद और गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंका।
- https://www.youtube.com/watch?v=n0bNYhPJnxk

लद्दाख की मांग पूरी होना

- राज्यों के बिल के पुनर्गठन के तहत एक ऐतिहासिक विधेयक पारित हुआ, जिससे कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया। इसके साथ ही लद्दाखवासियों के 70 वर्षों की मांग पूरी हुई।
- लद्दाख को एक अलग संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया जिसमें क्षेत्र की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से गंभीर सर्दी की अवधि के दौरान राज्य के अन्य क्षेत्र से कट जाने के कारण किसी विधायिका का प्रावधान नहीं रखा गया है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को लाभ पहुंचाना

- केंद्रीय कानून अब जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लागू हैं

अयोध्या का फैसला

- इस ऐतिहासिक निर्णय ने एक सदी से अधिक पुराने विवाद को समाप्त कर राष्ट्र में सामाजिक समरसता और सद्भावना उत्पन्न की।
- https://www.youtube.com/watch?v=bNAyGTOLzxU

बोडो समझौते पर हस्ताक्षर

- प्रधानमंत्री के विजन 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' ने एक और सफलता प्राप्त की।
- 50 वर्षों से अधिक बोडो संकट को समाप्त करने के लिए एक व्यापक समझौता किया।
- असम की क्षेत्रीय अखंडता आश्वस्त की गई।
- बोडो क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज।
- https://www.youtube.com/watch?v=QFf41Nek4X8
- https://www.youtube.com/watch?v=lfhMqYrdi0U

ब्रूयांग शरणार्थी संकट हल हुआ

- लगभग 34,000 आंतरिक रूप से विस्थापित हुए लोगों को त्रिपुरा में आवासित कराया गया।
- त्रिपुरा को ब्रूयांग शरणार्थियों के पुनर्वास और सर्वांगीण विकास के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए दिया जाना।

त्रिपुरा में आतंक का अंत

- त्रिपुरा में आतंक को समाप्त कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया गया।
- भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी-एसडी) द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019

- भारत के पड़ोसी देशों में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।
- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई
- पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान संरक्षित होगी

उत्तर-पूर्व, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) पर ध्यान केंद्रित करना

- नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) असम में प्रकाशित।

दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय

- इन राज्यों का विलय न केवल प्रशासनिक दक्षता में सुधार करेगा बल्कि प्रशासनिक व्यय को कम करेगा। इसके साथ ही इससे जनशक्ति का उपयोग उचित रूप से होगा, सेवा वितरण में सुधार होगा और योजनाओं की बेहतर निगरानी हो सकेगी। यह निर्णय अधिकारियों के बेहतर कैडर प्रबंधन को भी सुनिश्चित करेगा।

करतारपुर कॉरिडोर

- करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के माध्यम से सिख धर्म की समृद्ध संस्कृति का सम्मान करना और उसे बढ़ावा देना
- भारतीय मूल के सभी धर्मों के तीर्थयात्री इस कॉरिडोर का उपयोग कर सकते हैं
- यात्रा वीजा मुक्त होगी
- तीर्थयात्रियों को केवल एक वैध पासपोर्ट ले जाने की आवश्यकता है
- https://www.youtube.com/watch?v=rGMxbTq79yA

शस्त्र संशोधन अधिनियम

- अधिक सुरक्षित समाज के लिए फायरआर्म्स का बेहतर विनियमन।
- यह अधिनियम अवैध निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण और अवैध अधिग्रहण जैसे मौजूदा अपराधों के लिए सजा को बढ़ाता है। बारूद को रखना या ले जाना; फायरआर्म्स की अवैध तस्करी मानव जीवन को खतरे में डालने वाली गोलियां निषिद्ध हथियारों पर प्रतिबंध

रक्षा स्टाफ प्रमुख (सीडीएस) के पद का सृजन

- देश में उच्च रक्षा प्रबंधन में सुधार के लिए गए ऐतिहासिक निर्णय में, सरकार ने फोर स्टार जनरल के पद पर रक्षा स्टाफ प्रमुख (सीडीएस) के पद के सृजन को मंजूरी दी, जिसमें सेना प्रमुख के समकक्ष वेतन और अनुलाभ होंगे।
- तदनुसार जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को रक्षा स्टाफ प्रमुख (सीडीएस) का पद ग्रहण किया।
- रक्षा स्टाफ प्रमुख (सीडीएस) के रूप में, वह सभी तीनों रक्षा सेवाओं के मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार हैं और सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) के प्रमुख हैं।
- रक्षा स्टाफ प्रमुख (सीडीएस) की नियुक्ति 15 अगस्त, 2019 को प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की गई घोषणा के बाद की गई।

नेताजी की फाइलों तक सभी की पहुंच

- नेता जी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से संबंधित सभी अभिलेखों का विवर्गीकरण पूरा हो चुका है। सभी अभिलेख भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे गए हैं। नेताजी की फाइलें ऑनलाइन पोर्टल www.netajipapers.gov.in पर अपलोड की गई हैं

प्रधानमंत्रियों पर एक संग्रहालय

- भारत के प्रधानमंत्रियों के जीवन पर आधारित एक अत्याधुनिक संग्रहालय के निर्माण के लिए 226 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस संग्रहालय के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने वाले सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों, योगदानों और उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा।

यंग इंडिया वाइब्रेंट इंडिया

स्टार्टअप इंडिया

- स्टार्टअप नीति को शामिल करते हुए स्टार्टअप इंडिया विजन 2025 को व्यापक हितधारक परामर्शों के आधार पर तैयार किया गया है।
- राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (एनएसएसी) का गठन किया गया है
- स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत अब कुल 31,624 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है, जिनमें से 13,647 स्टार्टअप को 1 मई 2019 से मान्यता प्राप्त है।
- स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स प्रावधानों को वापस लिया गया।
- 266 स्टार्टअप्स को फरवरी 2020 तक आयकर अधिनियम की धारा 80 आईएसी के तहत छूट दी गई है

यंग इंडिया वाइब्रेंट इंडिया

पीएम ई-विद्या

- शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक पहल। यह पहल डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा के लिए मल्टी-मोड का उपयोग करने में सक्षम होगी।
- इससे देशभर में लगभग 25 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा।

मनोदर्पण

- मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए एक पोर्टल।

उच्च शिक्षा में ई-लर्निंग

- ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों का चयन ।
- पारंपरिक विश्वविद्यालयों और ओडीएल कार्यक्रमों में ऑनलाइन कंपोनेंट को वर्तमान 20% से बढ़ाकर 40% किया जाना है। विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लगभग 3.7 करोड़ छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

केंद्रीय और जवाहर नवोदय विद्यालयों को बढ़ावा देना

- 31 नए केंद्रीय विद्यालय खोले गए, 18 नए केवी भवनों का उद्घाटन और 7 नए केवी भवनों का शिलान्यास, 8 भवनों का निर्माण।
- पिछले एक वर्ष के दौरान 9 नए जवाहर नवोदय विद्यालयों को कार्यात्मक बनाया गया।
- उत्तराखंड के श्रीनगर के सुमरी गाँव में एनआईटी, उत्तराखंड का स्थायी परिसर स्थापित किया गया।
- निःशुल्क वर्दी: प्राथमिक स्तर पर बीपीएल, एससी और एसटी लड़कों को लड़कियों सहित निः शुल्क वर्दी के लिए 4716.81 करोड़ रुपये प्रदान किए गए (कक्षा एक से आठ तक)।
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें: प्राथमिक स्तर पर 9.9 करोड़ बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकों के लिए 3099.62 करोड़ रुपये प्रदान किए गए (कक्षा एक से आठवीं तक ब्रेल और दृष्टि दोष वाले बच्चों के लिए बड़े प्रिंट वाली किताबें)।
- मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षाः वर्ष 2019-20 के दौरान मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 120 करोड़ रुपये मंजूर किए गए और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए 71 करोड़ रुपये जारी किए गए।

यंग इंडिया वाइब्रेंट इंडिया

डिजिटल पहल:

- 'शगुन' : स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन शुरु किया गया। 1200 केन्द्रीय विद्यालयों, 600 नवोदय विद्यालय, 18000 अन्य सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों, 30 एससीईआरटी, 19000 एनसीटीई से संबद्ध संगठन, वेबसाइट के साथ शगुन एकीकृत है।

'ध्रुव'

- असाधारण प्रतिभाशाली छात्रों के मार्गदर्शन के लिए अनूठी पहल 'प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम - ध्रुव 'का शुभारंभ

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020

- केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 को पारित किया गया, जो 25 मार्च 2020 से लागू है।
- यह अधिनियम (i) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, (ii) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली और (iii) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करता है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2019

- दो नए विश्वविद्यालय- केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे।

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण)

- 9.7.2019 का नोटिफाई किया गया ताकि सेन्ट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक यूनिट मानकर रोस्टर बनाया जा सके

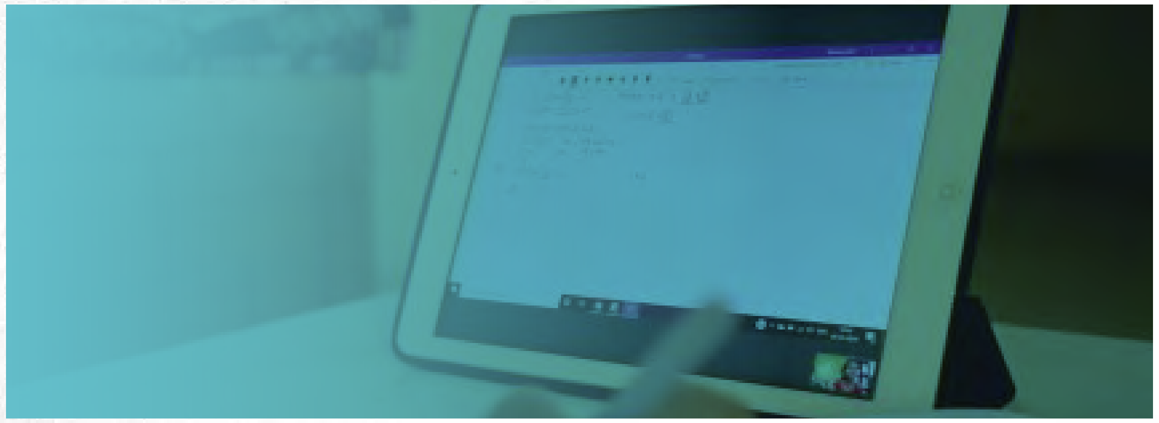

हमारे कामगारों के जीवन को गरिमापूर्ण बनाना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

- 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के असंगठित श्रमिकों, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना,
- इस योजना के तहत, अंशधारक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। श्रमिकों को 55 रुपये मासिक (18 वर्ष की आयु) योगदान करना पड़ता है और यह उम्र के अनुसार बदलता रहता है।
- इसके अलावा, यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रुप में प्राप्त करने का हकदार होगा।

ईपीएस और ईएसआई में संशोधन

- पेंशनभोगी जो पेंशन संराशीकरण के साथ पेंशन प्राप्त कर रहा है उनकी 15 वर्ष के बाद पेंशन संराशीकरण राशि बहाल कर दी जाएगी, जिससे 6.3 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा।
- श्रम मंत्रालय ने 2018-19 के लिए ईपीएफ पर 8.65% ब्याज दरों को अधिसूचित किया जो पहले 8.55% था। इससे करीब छह करोड़ ईपीएफ खाताधारकों को लाभ होगा।
- सरकार ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए ईएसआई अधिनियम के तहत योगदान की दर 6.5% से घटाकर 4% कर दी। इसका लाभ 3.6 करोड़ कर्मचारियों और 12.85 लाख नियोक्ताओं को होगा।

श्रम कानून

- प्रधान मंत्री के विजन के तहत द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुरुप केंद्रीय और राज्य श्रम कानूनों के बहुलता को 4 संहिताओं में सुव्यवस्थित किया जा रहा है। ये चार श्रम संहिताएं मौजूदा केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के समामेलन, सरलीकृत, और तर्कसंगत बनाने के द्वारा (i) मजदूरी; (ii) औद्योगिक संबंध; (iii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण; और (iv) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति पर आधारित हैं।

मजदूरी कोड 2019

- संसद के दोनों सदनों से पारित।
- मजदूरी कोड एक ऐतिहासिक क़ानून है, जो संगठित और साथ ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और समय पर मजदूरी के भुगतान के लिए वैधानिक संरक्षण सुनिश्चित करेगा।
- नया अधिनियम ऐतिहासिक है क्योंकि यह महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करता है और उनका पुरुष के समकक्ष समान मजदूरी सुनिश्चित करता है।
- कई असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे कृषि श्रमिकों, चित्रकारों, रेस्तरां और ढाबों में काम करने वाले व्यक्तियों और चौकीदारों, जो न्यूनतम मजदूरी के दायरे से बाहर थे, को न्यूनतम मजदूरी का विधायी संरक्षण प्रदान करेगा।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वर्किंग कंडीशन विधेयक 2019 संबंधी कोड

- यह कोड 10 या अधिक श्रमिकों और सभी खानों तथा बंदरगाहों के श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करने को विनियमित करने का प्रयास करता है।

श्रम सुधार

- मजदूरों के कार्य की तारतम्यता बनाए रखने के लिए निश्चित अवधि का रोजगार
- ईएसआईसी का योगदान 6.5% से घटाकर 4% किया गया
- वेब-आधारित और क्षेत्राधिकार-मुक्त निरीक्षण
- निरीक्षण रिपोर्ट 48 घंटों के भीतर अपलोड की जानी है
- 6 श्रम कानूनों के अनुपालन के संबंध में स्टार्ट-अप के लिए स्व प्रमाणन

सुरक्षा के सभी मामलों में अधिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर

रक्षा औद्योगिक गलियारा

- भारत सरकार ने रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को चिह्नित किया है।
- इस उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश के छह नोडल बिंदु अर्थात् अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट, झाँसी, कानपुर और लखनऊ को चिन्हित किया गया है।
- प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 2019 को झांसी (उत्तर प्रदेश) में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे की आधारशिला रखी।
- इसी प्रकार, तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा के लिए चेन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सलेम और तिरुचिरापल्ली नाम के पांच नोडल बिन्दु की पहचान की गई है।
- दोनों गलियारों ने पहले वर्ष में ही अच्छी प्रगति की है।
- उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव किए गए हैं और तमिलनाडु रक्षा गलियारा के लिए 3,100 करोड़ रुपये के प्रस्ताव किए गए हैं।

राइफल्स की एके सीरीज के उत्पादन, रखररखाव और विकास के लिए कलाश्निकोव, रूस और आयुध निर्माण बोर्ड का संयुक्त उद्यम

- राइफल एके-203 के उत्पादन और कम से कम 7,50,000 राइफल्स के भारत में इसके आशोधनों के लिए आयुध निर्माण बोर्ड, कलाश्निकोव और रोसोनबोरोन एक्सपोर्ट्स (दोनों रुस के) के बीच एक संयुक्त उद्यम का गठन किया गया। यह एके-203 राइफल्स का रखरखाव, संचालन और मरम्मत भी करेगा और उनकी तकनीकी सहायता के लिए आश्वस्त करेगा।
- नए अनुप्रयोगों के लिए राइफल्स के डिजाइन और विकास सहित संयुक्त आधुनिकीकरण, तीसरे पक्ष के उपकरणों के प्रतिस्थापन और अन्य कलाश्निकोव सीरीज के छोटे हथियारों के निर्माण सहित उन्नयन। तीसरे देशों के बाजार के लिए भारत में निर्मित राइफल्स एके-203 का संयुक्त विपणन और उनके लिए तकनीकी सहायता सुनिश्चित करना।

राफेल, अपाचे, चिनूक का समावेशन

- भारत को अक्टूबर 2019 में मध्यम मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल प्राप्त हुआ। उनमें से कुछ के इस वर्ष के अंत में भारत आने की उम्मीद है। यह भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता को बढ़ाएगा और इसके लड़ाकू स्क्वाड्रन ताकत में सुधार होगा।
- भारतीय वायु सेना को 17 अपाचे हेलीकॉप्टर भी मिले। अपाचे एक टेंडेम सीटिंग, दिन/रात, सभी मौसम के लिए एक सक्षम प्लेटफार्म है। यह अत्यधिक चुस्त है, जो युद्ध की क्षति के बाद भी सही स्थिति में रहता है और क्षेत्र की स्थितियों में भी आसानी से व्यवस्थित रखा जा सकता है।
- मार्च 2019 से चंडीगढ़ और मोहनबाड़ी में पंद्रह चिनूक हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। चिनूक का ओपी एक्स्पलॉइटेशन प्रारंभ हो गया तथा ओपी मेघदूत क्षेत्र में 15900 फीट में परीक्षण लैंडिंग पूरा किया गया।

नौ सेना में न्यू स्टीमर फ्रिगेट शामिल

- नेवी में पहला न्यू स्टीमर फ्रिगेट शामिल स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी आइ एन एस खंडेरी को कमिशन किया गया।
- नेवी का पहला जहाज 17A फ्रिगेट्स नीलगिरी लॉन्च किया गया।
- भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा ड्राई डॉक - एयरक्राफ्ट कॅरियर डॉक नेवल डॉकयार्ड को मुंबई में कमिशन किया गया।

अटल सुरंग

- पूर्ववर्ती रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 19 को "अटल सुरंग" कर दिया। इस 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग को सितंबर 2020 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। यह सड़क मनाली और लेह के बीच सड़क की 46 किलोमीटर की लंबाई को कम करेगी और लाहौल और स्पीति घाटियों को सभी मौसम में आपस में जोड़े रखेगी।

सबसे छोटा मानसरोवर यात्रा मार्ग

- उत्तराखंड से मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे छोटा मार्ग, राष्ट्र को समर्पित किया गया । गत्तीबाग से लिपुलेख की लंबाई 79 कि. मी. है जो 2020 से वाहन से तय की जाएगी ।

लद्दाख के लिए वैकल्पिक मार्ग: नीमू-पदम-दरचा रोड

- लद्दाख को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के लिए नीमू-पदम-द्वार (एन-पी-डी) सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वांगला के माध्यम से कनेक्टिविटी सितंबर 2020 तक की जाएगी। सभी मौसम में कनेक्टिविटी के लिए शिंकुनला दर्रे पर सुरंग प्रस्तावित है।

सेला सुरंग

- रणनीतिक रुप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग पर 20 जून को काम शुरु होगा ।
- जिसके मार्च 2022 तक पूरा करने की योजना है।

विश्व के पटल पर चमकता भारत

हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प

- हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प ने भारत - अमेरिका के रिश्ते और दोनों नेताओं के उत्साहवर्धक मैत्रीपूर्ण संबंधों को दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री दोनों ने आतंकवाद के विरुद्ध एक साथ काम करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धताएं व्यक्त कीं।

https://www.youtube.com/watch?v=csLfft9Ofns
https://www.youtube.com/watch?v=qR0pA4S0O8I
https://www.youtube.com/watch?v=IEQ2J_Z1DdA

वुहान स्पिरिट, ममल्लापुरम कनेक्ट

- भारत-चीन संबंधों में नए युग की शुरुआत
- वर्ष 2020 को भारत - चीन सांस्कृतिक संबंधों और विचारों के आदान-प्रदानके वर्ष के रुप में जाना गया। दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और भाईचारा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और अतिरिक्त विश्वास बहाल करने के उपायों की दिशा में काम किया जाएगा।

https://www.youtube.com/watch?v=xnjyXOI4QQM

प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत जुड़ाव कई द्विपक्षीय संबंधों में देखा गया

- मालदीवः चुनाव के बाद प्रधानमंत्री अपनी पहली विदेश यात्रा पर मालदीव गए वहां उन्होंने उनकी संसद को संबोधित किया और उन्हें मालदीव का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार - ऑर्डर ऑफ निशानइज़्ज़ुद्दीन दिया गया।
- श्रीलंकाः प्रधानमंत्री ने सेंट एंथोनी जाकर वहां के नागरिकों के लिए एकजुटता दिखाई। इस स्थान मेंईस्टर के दौरान बम विस्पोट हुए थे। ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री पहले वैश्विक नेता है।
- भूटानः प्रधानमंत्री ने मंगदेछु पनबिजली संयंत्र का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने लोटे टीशेयरिंग के साथ बातचीत की।
- सउदी अरबः प्रधानमंत्री ने हाई-प्रोफाइल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में मुख्य भाषण दिया और व्यापक द्विपक्षीय चर्चा की।
- यूएईः प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया इसके लिए उन्हें यूएई का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया।
- बहरीनः बहरीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और उन्होंने वहां अंतरिक्ष, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और रुपे कार्ड संबंधी 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- राष्ट्रपति मैक्रोन और चांसलर मर्केल के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

आरसीईपी के संबंध में मजबूती से अपनी बात रखी

- वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी के दबाव पर आए कार्य किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम पारस्परिक सहयोग की भावना के साथ कार्य करते हैं लेकिन अपने हितों का त्याग नहीं कर सकते।
- उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने अन्य देशों के बाजारों के लिए हमारे देश का दरवाजा तो खोला लेकिन उनके बाजार खोलने में विफल रही।
- इस से आरसीईपी देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ा और 2004 में 7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ जो 2014 में बढ़ कर 78 बिलियन हो गया।
- आरसीईपी को नकार कर प्रधानमंत्री मोदी इस क्षति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और वे गरीबों किसानों, डेरी और एम एस एम ई क्षेत्रों के हितों का ध्यान रख रहे हैं।

बहुपक्षीय सम्मेलनों में चमकता भारत

- किर्गिस्तान में एस सी ओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक गहरा प्रभाव छोड़ा जब उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध बात की और इसके संबंध में वैश्विक सहमति बनाने की मांग की।
- जापान में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के लाभों पर प्रकाश डाला और ओसाका ट्रैक से बाहर रखकर भारत के डाटा हितों को सुरक्षित किया।
- ब्राजील में 11वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बोलसोनारों को 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रुप में आमंत्रित किया और अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
- रुस में आयोजित इकनॉमिक फोरम के सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने फॉर ईस्ट रीजन को उर्जा संपन्न क्षेत्र बनाने के लिए एक बिलियन डॉलर के रणनीतिक निवेश का वादा किया। इसके साथ ही उन्होंने अगले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन के 75वे विक्ट्री डे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में भाग लेने का आमंत्रण स्वीकारा।

पाकिस्तान को वैश्विक रूप से अलग कर आतंकवाद को उसकी जगह दिखाई

- पाकिस्तान को एफ ए टी एफ में ब्लैक लिस्ट कराने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया इसके साथ ही एशिया पेसिफिक सब ग्रुप ने भी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला किया और पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस देने के लिए मजबूर किया।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रों से न्यूनतम समर्थन भी नहीं मिलने के बाद पाकिस्तान कश्मीर मुद्दा उठाने में विफल रहा।
- भारत ने सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्यों के साथ यू एन जी ए के प्लस डोर सेशन में अपनी राजनीतिक उत्तराधिकारी का पूर्ण प्रदर्शन किया।

गगनयान - 21 वीं सदी में भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि

- भारतीय वायु सेना से चार पायलटों को गगनयान मिशन के लिए चुना गया और उनकी ट्रेनिंग रूस में आगामी दिनों में होगी।
- इस मानवयुक्त मिशन के बाद भारत रूस, अमरीका और चाइना के बाद मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने चौथा देश बन जाएगा।
- गगनयान भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लांच किया जाएगा।
- इन भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले दो टेस्ट अंतरिक्ष मिशन को प्लान किया गया है।

5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम

नागरिक उड्डयन में एफडीआई

- एयर इंडिया लिमिटेड के मामले में उन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है जो एन आर आई हैं।

कॉर्पोरेट टैक्स में कमी

- नई बिजली उत्पादन कंपनियों के लिए 15% टैक्स रेट की दर बढ़ाई गई।
- भारती कॉर्पोरेट टैक्स की दरें अभी दुनिया में सबसे कम है।

कॉरपोरेट अफेयर्स

- 1 दिन में कंपनी खोलने की सुविधा जिसमें कंपनी के नाम का आरक्षण निगमन के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर।
- इंटीग्रेटेड इनकॉरपोरेशन फोरम
- सिर्फ 16 ऑफेंस सेक्शन को ही मॉनिटरी पेनल्टी में बदला गया
- विलय और अधिग्रहण के लिए त्वरित और आसान अनुमोदन
- डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के प्रावधानों में संशोधन
- कंपनी एक्ट के तहत 14000 प्रॉसीक्यूशन का विड्रॉल
- एमएसएमई और होमबायर्स के सहयोग के लिए आईबीसी फ्रेमवर्क में संशोधन।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय

- दस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का चार यानि पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक में समेकन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग परिदृश्य को बदल कर रख दिया है।
- विलय के बाद डिजिटल तकनीक से लैस ये बैंक व्यापार को और सुगम बनाएंगें एवं वैश्विक पटल पर इनका असर और बढ़ेगा

विनिवेश और निजीकरण

- चुनिंदा CPSEs में रणनीतिक विनिवेश- भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, CONCOR टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मिनिरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, MECON और नीलांचल इस्पात निगम समिति को मंजूरी दी गई।

एनबीएफसी ऋण पर अधिस्थगन

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च, 2020 तक सभी ऋणों के साथ-साथ कार्यशील पूंजी सुविधाओं के बकाया पर तीन महीने की मोहलत की घोषणा की।
- कोविड-19 के कारण ऋण सेवाओं में बढ़ते बोझ को कम करने के लिए कुछ नियामक उपायों की घोषणा की गई है।
- सभी टर्म लोन (कृषि खरीद ऋण, खुदरा, फसल ऋण और पूल खरीद के तहत ऋण) और नकद क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट, पैकेज के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- सावधि ऋण किस्तों के पुर्नभुगतान को बढ़ाकर सभी उधारकर्ताओं को बोर्ड में सुविधा प्रदान की गई।
- सावधि ऋणों के लिए मूल पुनर्भुगतान अवधि 90 दिनों तक बढ़ जाएगी अर्थात 1 मार्च 2025 को परिपक्व होने वाली 60 किश्तों में देय ऋण 1 जून 2025 को परिपक्व होगी।

कंपनी अधिनियम में संशोधन - ईमानदार व्यवसाय करने में सुगमता

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, सरकार ने कंपनी अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 पेश किया।
- इस अधिनियम के तहत होस्ट ऑफ ऑफेन्स से आपराधिकता को हटाने के लिए अधिनियम में 72 से अधिक बदलावों का प्रस्ताव है और भारतीय कंपनियों की प्रत्यक्ष विदेशी सूची के लिए मार्ग प्रशस्त करता है
- इससे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को शीघ्रता से निपटाया जा सकेगा। इस विधेयक से कानून का पालन करने वाले कॉरपोरेटस को भी आसानी होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स के विनिर्माण को बढ़ावा

- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों (एसपीईसीएस) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना:
  - इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करने वाले सामानों के विनिर्माण के लिये सरकार पूंजीगत व्यय का 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
  - यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों के घरेलू विनिर्माण के लिए असमर्थता को दूर करेगा।
- अनुमोदित इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स (ईएमसी) के माध्यम से सामान्य सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास के लिए संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी2.0) योजना को वित्तीय सहायता।
- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना के लिए उत्पादन संयोजक प्रोत्साहन घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा और मोबाइल फोन निर्माण और एकत्रण, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों सहित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करेगा। यह योजना भारत में निर्मित वस्तुओं के वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष) पर 4% से 6% तक की प्रोत्साहन राशि बढ़ाएगी और लक्षित क्षेत्रों के तहत कवर की जाएगी।

सिविल दायित्व के लिए सीएसआर उल्लंघन कम करना

आपराधिक कार्य नहीं माना जाएगा और इसके बजाय नागरिक दायित्व होगा।

मजबूत इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड

- संशोधन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 में कुछ अस्पष्टताओं को दूर करेगा और संहिता का सुचारु क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
- संशोधनों के तहत, कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया के शुरु होने से पहले किए गए अपराध के लिए एक कॉर्पोरेट देनदार का दायित्व समाप्त हो जाएगा, और सहायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रिज़ॉल्यूशन प्लान को उस तारीख से मंजूरी नहीं दी जाएगी जिस दिन रिज़ॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दी गई है।

एमएसएमई - स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन

- स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों की वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viiबी) डीपीआईआईटी के साथ पंजीकृत स्टार्टअप पर लागू नहीं होगी।
- स्टार्टअप्स की समस्याओं के समाधान के लिए सदस्य, सीबीडीटी के तहत एक समर्पित सेल स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। किसी भी आयकर मुद्दे पर एक स्टार्टअप उसके त्वरित समाधान के लिए सेल से संपर्क कर सकता है।
- एमएसएमई के लिए एक कारखाना स्थापित करने के लिए एकल वायु और जल निकासी और एकल सहमति
- ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर 1 करोड़ रुपये तक के ऋण को सैद्धांतिक मंजूरी। कुल 1,59,422 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 4,9,330 करोड़ रुपये शामिल हैं। अक्टूबर 2019 तक 7,106 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।
- जीएसटी के लिए 2 करोड़ रुपए तक की वृद्धिशील क्रेडिट पर 2 प्रतिशत का ब्याज सबवेंशन। एसआईडीबीआई ने नवंबर 2018 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए 43 बैंकों / एनबीएफसी से 8 करोड़ रुपए का दावा और निपटान किया है।
- सभी कंपनियाँ जिनका टर्नओवर प्लेटफार्म पर अनिवार्य रुप से 500 करोड़ रुपये से अधिक है, वे उद्यमियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। अब तक 329 कंपनियों ने टीआरईडीएस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।
- सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) अनिवार्य रुप से एमएसएमई से अपनी कुल खरीद का कम से कम 25 प्रतिशत खरीद करते हैं। सीपीएसयू ने 59,903 एमएसएमई से 15,936.39 करोड़ की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की है।

- एमएसएमई से अधिदेशित 25 प्रतिशत खरीद में से 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है। 2019-20 के दौरान, एमएसएमई के स्वामित्व वाली 1,471 महिलाओं से 2242 करोड़ रुपये की खरीद की गई है।
- 20 प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) और 100 विस्तार केंद्र (ईसी) 6,000 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किए जाने हैं। इन टीसी और ईसी की स्थापना के लिए Rs.99.30 करोड़ जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 में दस और ईसी की योजना बनाई गई है।
- फार्मा क्लस्टर की स्थापना के लिए लागत का 70 प्रतिशत सरकार वहन करती है। फार्मा क्लस्टर्स और सामान्य सुविधाओं के विकास के लिए सोलन, इंदौर, औरंगाबाद और पुणे के चार जिलों को चुना गया है।
- वर्ष में एक बार दायर किए जाने वाले आठ श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय विनियमों के तहत रिटर्न।
- एक निरीक्षक द्वारा दौरा किए जाने वाले प्रतिष्ठानों को एक कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिक आवंटन के माध्यम से तय किया जाएगा। 3,080 निरीक्षण किए गए हैं और सभी निरीक्षण रिपोर्ट श्रम सुविधा पोर्टल पर अपलोड की गई हैं।

व्यापारी पेंशन योजना

- 60 वर्ष की आयु वाले छोटे व्यापारियों (दुकानदारों/खुदरा व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों) को 3000 / - रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन ।
- इस योजना के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम, के साथ 18-40 वर्ष की आयु के व्यापारी पात्र हैं।
- लगभग 3 करोड़ छोटे व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लाभान्वित होने की उम्मीद।

नई आय कर व्यवस्था

- कुछ आयकर अधिकारियों द्वारा नोटिस, समन, आदेश आदि के मुद्दे पर उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने के लिए:
- 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद आयकर अधिकारियों द्वारा सभी नोटिस, सम्मन, आदेश आदि एक केंद्रीकृत कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाएंगे और इसमें एक कंप्यूटर जनरेटेड अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या होगी।
- कंप्यूटर जनरेटेड यूनीक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना जारी किया गया कोई भी संचार गैरकानूनी होगा।
- सभी पुराने नोटिस 1 अक्टूबर 2019 तक तय किए जाएंगे या फिर सिस्टम के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे
- 1 अक्टूबर, 2019 से उत्तर की तारीख से तीन महीने के भीतर सभी नोटिसों का निपटान किया जाएगा।

अनियमित जमाकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाना

- संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अनारक्षित जमा योजना अधिनियम 2019 पर प्रतिबंध। नया अधिनियम देश में गैरकानूनी जमा करने वाली गतिविधियों के खतरे से निपटने में मदद करेगा, जो वर्तमान में विनियामक अंतराल का शोषण कर रहे हैं और गरीबों और उनकी मेहनत की बचत से भोले-भाले लोगों को लुभाने के लिए सख्त प्रशासनिक उपायों का अभाव है।

उपभोक्ताओं को व्यापक संरक्षण

- एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं को व्यापक सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मोदी 2.0 सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया।
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना
- उपभोक्ता आयोगों में स्थगन प्रक्रिया को सरल करता है

इनोवेशन इंडेक्स पर आगे बढ़ना

- भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में 5वें पायदान से छलांग लगाकर 52वें स्थान पर पहुंच गया।

भारत एक बड़ा पर्यटक आकर्षण केन्द्र बना

- विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (टीटीसीआई) में भारत 2013 में 65वीं रैंक से 2019 में 34वीं रैंक पर पहुंच गया।
- पर्यटकों द्वारा प्रवेश टिकट खरीदने की सुविधा के लिए एएसआई के टिकट वाले स्मारकों पर क्यूआर कोड की स्थापना
- एएसआई की विरासत स्मारकों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फिल्म की शूटिंग आदि के लिए अनुमति ऑनलाइन की गई।
- स्मारकों के भीतर पर्यटकों का मार्गदर्शन करने के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया गया ।
- भारत की समृद्ध, मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत संस्कृति वेब पोर्टल का शुभारंभ।

नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देना

- कुतुब मीनार और सफदरजंग मकबरे सहित एएसआई के ऐतिहासिक स्मारकों में रात की रोशनी की व्यवस्था।
- पर्यटकों के लिए रात 9 बजे तक बड़े पर्यटन स्थल के साथ कई स्मारक खोलने का निर्णय लिया गया

अंतर्राष्ट्रीय सम्मान

- जयपुर शहर भारत का 38वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया
- नेशनल कल्चरल ऑडियो विजुअल आर्काइव्स (एनसीएए) को विश्व के पहले भरोसेमंद डिजिटल रिपोजिटरी के रुप में प्रमाणित किया गया है। एनसीएए के पास अप्रकाशित गैर-वाणिज्यिक ऑडियो और विज़ुअल रिकॉर्डिंग/अभिलेखागार के मूल्यवान 31500 घंटे हैं।

स्मरणोत्सव

- गुरु नानक देवजी की जयंती के 550 वर्ष पूरे होने का उत्सव देश और विदेशो में मनाया जा रहा है |
- भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल, जलियांवाला बाग के पुनर्विकास और अमृतसर, पंजाब में जलियांवाला बाग स्मारक के जीर्णोद्धार के साथ मनाया जा रहा है।

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जा रही है और साथ ही साथ उनके विचारों और दर्शन के प्रचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाई जा रही है।
- महात्मा गांधी पर डिजिटल प्रदर्शनी गांधी स्मृति, नई दिल्ली में स्थापित की गई और गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली सहित 16 अन्य स्थानों पर भी इसका प्रदर्शन किया गया।
- आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी गांधीनगर के सहयोग से गांधीपीडिया विकसित किया जा रहा है।
- पदयात्रा, रैलियां, नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरियां, सर्व धर्म सभा, गांधी कथा, ग्राम स्वराज पदयात्रा, कलाकारों की आंखों के माध्यम से बापू नामक गांधी पर पेंटिंग प्रदर्शनी और गांधी ग्लोबल प्ले भारत भाग्य विधाता देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए गए।
- 'शांति सूत्र' नामक नृत्य महोत्सव का मंचन भारत के त्योहार के हिस्से के रुप में प्रिटोरिया, डरबन, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया।

https://www.youtube.com/watch?v=ssUhq_oJuT0
https://www.youtube.com/watch?v=5_JpKC-6-0I
https://www.youtube.com/watch?v=8rTPeNWFY4U

- **रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के बजट मे 40,000 करोड़ की वृद्धि।**
  - कुल मिलकर लगभग 300 करोड़ व्यक्ति दिवस के बराबर रोजगार कर सृजन होगा।
  - लौट रहे प्रवासी मजदूरों को अधिक रोजगार की मांग को पूरा करेगा।
  - जल संरक्षण परिसंपत्तियों सहित टिकाऊ और आजीविका संबंधी परिसंपत्तियों का बड़ी संख्या में सृजन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।

- **CAMPA के माध्यम से वन और वन्यजीव संसाधनों को विकसित करने के लिए राज्यों को मदद**

  शहरी, अर्ध-शहरी और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) कोष के तहत 6000 करोड़ रुपये।

  केंद्र सरकार के स्तर पर एड-हॉक लेवल पर पड़े हुए 47,870 करोड़ रुपये वन और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को हस्तांतरित जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करते हैं।

- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम-**

  प्रभावी वायु प्रदूषण में कमी की योजना 102 गैर-प्राप्ति शहरों से वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर बनाई गई है। संबंधित शहरों को आवंटित धन; NCAP के साथ के SPCB के तहत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का गठन और राज्यों के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। उच्च प्रदूषण स्तर वाले बड़े शहरों में विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजना के जरिये विशेष ध्यान देने की तैयारी

- **संरक्षित क्षेत्रों के आसपास इकोसेंसिटिव जोन-**

  31/3/2020 तक चिन्हित कुल ESZ (इकोसेंसिटिव जोन): 662 में से 400 को अधिसूचित। 2019-20 में ESZ (इकोसेंसिटिव जोन) -88 (वित्त वर्ष 2018-19 में 27 के मुकाबले)

- **पश्चिमी घाट:**

  भूस्खलन और बाढ़-ग्रस्त नक्शे के जरिये वैज्ञानिक विश्लेषण संबंधित राज्यों में किया गया

IFFI का गोल्डन ज्यूबली कार्यक्रम गोवा में धूमधाम से आयोजित किया गया।

ICFT-UNESCO द्वारा IFFI के लिए 50 वर्ष पुरे करने पर फेलिनी मंडल की घोषणा की गयी।

ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन और NFAI द्वारा अपनी तरह की हाईटेक डिजिटल इंटरैक्टिव प्रदर्शनी का आयोजन गोवा में किया गया।

अन्नदाता किसान का कल्याण

कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय सहायता में छलांग

कृषि के लिए बजटीय समर्थन में क्वांटम छलांग:

- 2019-2020 में, बजटीय आवंटन 130485.21 करोड़ था, जो कि 2018-19 में 46700 करोड़ रुपये के परिव्यय से रिकॉर्ड छलांग है।
- 2020-21 के लिए आवंटन बढ़ कर 134399.77 करोड़ हो गया।

कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि

- **खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि:**

  भारत ने 2018-19 में कुल 285.20 मिलियन टन का उत्पादन प्राप्त किया और 2019-20 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, खाद्यान्न का उत्पादन 291.95 मिलियन टन होने का अनुमान है जो 2.36% की वृद्धि दर्शाता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (प्रधानमंत्री-किसान) योजना

- मोदी सरकार ने देश भर में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से फरवरी 2019 में किसानों के लिए एक अग्रणी आय समर्थन प्रोत्साहन शुरु किया।
- प्रति वर्ष 6000/- रुपए की आय सहायता, लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाती है, जो कि 2000/- रुपए की तीन किस्तों में होती है।
- 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित

लाभ:

- सबसे कमजोर किसान परिवारों को पूरक आय प्रदान करता है
- खासकर फसल के मौसम से पहले उनकी उभरती जरुरतों और खर्चों को पूरा करता है।
- इस प्रकार उन्हें साहूकारों से बचाता है जो खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करते हैं।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाई)

- सितंबर 2019 में प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाइ) की शुरुआत के साथ, मोदी सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार किया।
- यह 60 वर्ष की आयु वाले पात्र लघु और सीमांत किसानों को 3,000/- रुपए की न्यूनतम निश्चित पेंशन को सुनिश्चित करता है।
- इस योजना के तहत 01.05.2020 तक 20,17,788 किसानों को पंजीकृत / नामांकित किया गया है

ब्याज अनुदान योजना(आईएसएस)

- कृषि के लिए संस्थागत ऋण 2019-20 में 13.50 लाख रुपए से बढ़ कर 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए हो गया।
- ब्याज अनुदान योजना के तहत दावों के निपटारे के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आरबीआई/नाबार्ड को 16,218.75 करोड़ रुपये जारी किए गए।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी)

- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के साथ सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को कवर करने के लिए फरवरी, 2020 में विशेष अभियान शुरु किया गया।
- अब तक प्राप्त लगभग 75 लाख नए आवेदनों में से 22 लाख केसीसी स्वीकृत।
- वर्तमान में 6.75 करोड़ सक्रिय केसीसी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

- 2018-19 में बजट की घोषणा के बाद से 2017-18 की तुलना में 2018-19 में अधिकांश अनिवार्य फसलों के एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- 2018-19 की तुलना में, सोयाबीन के लिए एमएसपी में 2019-20 में सबसे ज्यादा 9.1% और उसके बाद रागी (8.7%) और मसूर (7.3%) में वृद्धि हुई।

जम्मू और कश्मीर में सेब की खरीद

- विभिन्न किस्मों के सेब 31.03.2020 तक की खरीद अवधि के दौरान एमआईएस के तहत जम्मू और कश्मीर में 69.38 करोड़ रुपए की खरीद हुई।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

- चरण -2 में 2018-19 से 2019-20 के दौरान 9.52 लाख किसानों को लाभ हुआ।
- इसके अंतर्गत विभिन्न ब्रांड विकसित हुए: मध्य प्रदेश-मेड इन मंडला; उत्तराखंड-जैविक उत्तराखंड; तमिलनाडु-तमिलनाडु जैविक उत्पाद (टीओपी); महाराष्ट्र-साही जैविक, नासिक जैविक और गढ़चिरोली जैविक खेती; झारखंड -जैविक झारखंड, झारखंड की भूमि से; छत्तीसगढ़- भूमिगड़ी एफपीओ का आदिम ब्रांड, बस्तर नैचुरल; पंजाब- पाँच नदियाँ; त्रिपुरा-त्रिपुरेश्वरी फ्रेश।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

- 2019-20 में, प्रायोगिक प्रोजेक्ट ;डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजेज; के तहत प्रति ब्लॉक एक गांव को गोद लिया गया जिसमे भूमि पर आधारित मृदा नमूनाकरण, परीक्षण और अधिक से अधिक 50 प्रदर्शनों(प्रत्येक 1 हेक्टेयर) की अधिकतम संख्या के प्रदर्शनों के संगठन के लिए अपनाया गया था
- राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के सभी 6954 गाँवों में, 23 लाख नमूनों के लक्ष्य के विरुद्ध, 15.69 लाख नमूनों का विश्लेषण और 14.66 लाख कार्ड किसानों को वितरित किए गए।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर)

- वर्ष 2019-20 में 103.80 करोड़ रुपये जारी।
- चरण- II में 2018-19 से 2019-20 के दौरान 28971 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया।
- योजना के तहत विभिन्न ब्रांड विकसित किए गए: ऑर्गेनिक अरुणाचल, ऑर्गेनिक मणिपुर, ऑर्गेनिक मिजोरम, नागा ऑर्गेनिक, सिक्किम ऑर्गेनिक।

किसानों को बाजार से जोड़ना

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) - किसानों को बाजार से जोड़ना

- कुल 962 ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर जुड़ी।
- मई 2019 से अप्रैल, 2020 के दौरान, कुल 98.21 लाख टन एमटी विभिन्न कृषि वस्तुओं और नारियल और बांस जैसी वस्तुओं के अलावा, जो संख्या में कारोबार किया जाता है (संख्या में 3.16 लाख) 32,551.74 करोड़ रुपये की कीमत ई-एनएएम पोर्टल पर दर्ज की गई है।

किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ)

- फरवरी 2020 में, प्रधान मंत्री ने पांच साल की अवधि (2019-20 से 2023-24) में 10,000 नए एफपीओ बनाने और बढ़ावा देने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन; योजना शुरु की।
- गठन से पांच साल तक प्रत्येक एफपीओ को पर्याप्त हैंड होल्डिंग प्रदान करते हुए वर्ष 2027-28 तक समर्थन जारी रहेगा।

ई-एनएएम पर एफपीओ

- मई 2019 से मई 2020 के दौरान ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर 257 एफपीओ ऑन-बोर्ड किए गए।
- योजना शुरु होने के बाद से 16 राज्यों के 1005 एफपीओ को ई-एनएएम पर पंजीकृत किया गया है।

एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल

- एफपीओ को संग्रह केंद्रों से उपज के चित्रों आदि के साथ अपलोड करने में सक्षम बनाने और मंडियों में जाए बिना बोली सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल, 2020 में आरंभ किया गया।
- अब तक 8 राज्यों में एफपीओ संग्रह केंद्र के माध्यम से 135 एफपीओ कारोबार किया गया।

लॉजिस्टिक का उबेराइजेशन

- व्यापारियों को एक मंडी से विभिन्न अन्य स्थानों पर उत्पादन की तेज आवाजाही के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध ट्रांसपोर्टर्स को खोजने में व्यापारियों की मदद करने के लिए 11.37 लाख से अधिक ट्रक और 2.31 लाख ट्रांसपोर्टर्स ई-एनएएम पोर्टल से जुड़े हुए हैं ।

कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई):

- 2019-20 में 8,73,818 मीट्रिक टन क्षमता वाले 419 स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गयी।
- योजना के तहत 34 कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाएँ (भंडारण के अलावा) भी स्वीकृत की गईं।

कृषि विपणन सुधार

- प्रत्यक्ष विपणन की सुविधा के लिए राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार किसानों / एफपीओ / सहकारी समितियों आदि से प्रत्यक्ष खरीद को सक्षम करना।
- अब तक, 22 राज्यों ने कृषि उपज के प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति दी है।
- अब व्यापारी किसानों की उपज सीधे फार्म गेट से खरीद सकते हैं और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मंडी आने की आवश्यकता नहीं है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: प्रति बूंद अधिक फसल (पी एम के एस वाई-पी डी एम सी):

- सटीक/ सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- एक वर्ष के दौरान सूक्ष्म सिंचाई के तहत 8.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया।
- सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा के लिए नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई निधि का सृजन ।

बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एम आई डी एच)

- उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों (एच एम एन ई एच) के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) और बागवानी मिशन के तहत 1.21 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र कवर किया गया।
- इ ग्राम स्वराज - प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 25 अप्रैल 2020 के दिन इ ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप को लॉंच किया।
- इस पोर्टल के जरिये सरकार द्वारा नई पहल की गई जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत अपने विकास कार्यों से जुड़े डेटा को सिंगल इंटरफेस के जरिये तैयार कर पाऐंगे।

यात्रियों की सुरक्षा

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019

- सड़क सुरक्षा, नागरिक सुविधा, पारदर्शिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से भ्रष्टाचार को कम करना और बिचौलियों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण बदलाव ।
- सार्वजनिक परिवहन को मजबूत, अच्छे समारिटन्स की सुरक्षा और बीमा और क्षतिपूर्ति व्यवस्था में सुधार करता है।
- दिव्यांग लोगों को सुविधा प्रदान करता है कि वे मोटर वाहनों को पोस्ट-फैक्टो अनुमोदन के साथ अनुकूलित वाहनों में परिवर्तित होने दें और अनुकूलित वाहनों को चलाने के लिए लाइसेन्स की सुविधा प्रदान करता है।
- दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए किए जाने वाले उपाय।

छोटे व्यापारियों का कल्याण

प्रधान मंत्री लघु व्यापार मान धन योजना

- 60 वर्ष की आयु वाले लघु व्यापारियों (दुकानदारों/ खुदरा व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों) को 3000 / - रु की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन ।
- लगभग 3 करोड़ छोटे व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लाभान्वित होने की उम्मीद।

कौशल विकास

कौशल भारत मिशन

- कुशल कार्यबल की मांग को पूरा करने के लिए कौशल भारत मिशन के तहत पिछले एक वर्ष में एक करोड़ से अधिक युवाओं को कुशल बनाया गया ।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी एम के वी वाई)

- पीएमकेवीवाई के तहत पिछले एक वर्ष में 37 क्षेत्रों में 52 लाख उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण लिया।

प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पी एम के के)

- पिछले एक वर्ष में 133 जिलों में 136 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले गए।

विकास के इंजन को बढ़ावा देना -रेलवे

बढ़ी हुई सुरक्षा

- पिछले वर्ष शून्य यात्री मृत्यु दर के साथ सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रदर्शन।
- 2019-20 में 1274 मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग समाप्त हो गईं जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी है। यह लेवल क्रॉसिंग की अब तक की सर्वोच्च समाप्ति है।
- 2018-19 में 4,265 ट्रैक किमी के मुकाबले 2019-20 में 5,181 ट्रैक किमी के लिए रेल का उच्चतम नवीकरण जो पिछले वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक है।
- सेल (SAIL) से वर्ष के दौरान रेल (13.8 लाख टन) की उच्चतम आपूर्ति।
- 2019-20 के दौरान मैकेनिकल सिग्नलिंग वाले 84 स्टेशनों को इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग से बदल दिया गया।
- ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार।

रोलिंग स्टॉक उत्पादन में वृद्धि

- वित्त वर्ष 2018-19 में 605 की तुलना में 30% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 में 785 इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन ।
- वित्त वर्ष 2018-19 में 4,429 की तुलना में 42% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2019-20 में 6,277 एलएचबी कोच का उत्पादन।

रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर

- 2019-20 संसोधित अनुमान में 1,61,351 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय। । यह 2018-19 की तुलना में 20.1% की वृद्धि है।
- नई लाइन, दोहरीकरण और गेज रुपांतरण संचालन 2019-20 में बढ़कर 2,226 किमी हो गया।

रेलवे विद्युतीकरण:

- वित्त वर्ष 2019-20 में कुल 5,782 किलोमीटर का रेलवे विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है।

समर्पित फ्रेट कॉरिडोर फास्ट ट्रैक:

- ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों पर शीघ्रता से काम।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में रेवाड़ी - मदार (306 किलोमीटर) सेक्शन का पश्चिमी डीएफसी और खुर्जा में - पूर्वी डीएफसी के भदान (194 किमी) सेक्शन का काम पूरा हो गया और मालगाड़ियों का परिचालन शुरु हो गया।

यात्री सेवाओं में सुधार

- वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2 तेजस ट्रेनें आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ दिल्ली-लखनऊ और मुंबई के बीच शुरु की गईं।
- नई दिल्ली से कटरा के बीच नियमित सेवा में शामिल होने के साथ आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ द्वितीय वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ।
- 2019-20 में उत्कृष्ट मानक पर 289 ट्रेनें अपग्रेड की गई । अब तक कुल 385 अपग्रेड की गईं हैं।
- 134 नई ट्रेनों की शुरुआत की गई, 118 ट्रेनों की सेवाओं को बढ़ाया गया और 22 ट्रेन सेवाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई।

स्वच्छ भारत, स्वच्छ रेलवे

- 2019-20 के दौरान 14,916 कोच में 49,487 बायो-टॉयलेट लगाए गए। यह लगभग 99.3% की कवरेज के साथ 68,800 कोचों में लगे 2,45,400 बायो-टॉयलेट्स की संचयी संख्या है।
- 2 अक्तूबर 2019 को 150 वीं गांधी जयंती से सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्री का उपयोग बंद।

स्टेशनों पर यात्रियों के लिए जनसुविधाएं

- 2019-20 में जारी भारतीय रेलवे के विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश।
- 2019-20 में सुगम्य भारत अभियान के एक भाग के रूप में भारतीय रेलवे में 80 एस्केलेटर और 83 लिफ्ट प्रदान की गई हैं। अब तक आईआर पर 742 एस्केलेटर और 571 लिफ्ट प्रदान किए गए हैं।
- 609 रेलवे स्टेशनों को 2019-20 के दौरान बेहतर रोशनी का स्तर प्रदान किया गया।
- वित्त वर्ष 2019-20 में 268 फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) प्रदान किए गए।
- 5628 स्टेशनों को वाई-फाई प्रदान किया गया (वित्त वर्ष 2019-20 में 4058 स्टेशनों में दिए गए).

फास्ट लेन में माल ढुलाई

- 2018-19 के दौरान शामिल 9535 वैगनों की तुलना में 2019-20 के दौरान 11386 नए वैगनों को शामिल किया गया।
- कुल 1268 फ्रेट ग्राहक अब नवंबर 2019 से ई-भुगतान सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

सुरक्षित रेलवे

- रेलवे में आतंकवाद और नक्सलवाद के खतरे से निपटने के लिए पहली रेलवे कमांडो बटालियन 'कोरस' का शुभारंभ।
- 585 स्टेशनों पर सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली के साथ उपलब्ध कराए गए जिनमें से 132 स्टेशनों पर सीसीटीवी 2019-20 में प्रदान किए गए ।

क्वालिटी फूड

- आईआरसीटीसी की रसोई इकाइयों के सीसीटीवी के माध्यम से वेब-आधारित लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा 18 रसोई इकाइयों (मई, 2019) से बढ़ कर 43 रसोई इकाइयों तक विस्तारित हुई।

आरसीएस उड़ान

- इंदौर (मध्य प्रदेश) से किशनगढ़ (अजमेर, राजस्थान) के लिए पहली-तीन बार साप्ताहिक उड़ान।
- देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपेड से गौचर, और चिन्यालीसौड़ तक क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत पहली बार हेलीकाप्टर सेवाएं - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान)
- कर्नाटक के बीदर हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए पहली सीधी उड़ान।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का निर्माण

- कुल 82 खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला परियोजनाएं संचालित की गईं।
- 82 पूर्ण की गई परियोजनाओं में 1570 करोड़ रु के निजी निवेश का लाभ उठाया गया और 40,600 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा किया।

कोविड-19 शिकायत निवारण

- लॉकडाउन के दौरान उद्योग का समर्थन करने के लिए निवेश भारत के साथ एमओएफपीआई द्वारा एक कोविड शिकायत सेल की स्थापना की गई थी।
- 20 मई, 2020 तक कुल 585 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 577 का समाधान/ बंद किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस

- सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना प्रस्तावित की गई।
- इसका मुख्य उद्देश्य सोलर एनर्जी में सुचारु उपयोग को बढ़ावा देना है।

सामाजिक क्षेत्र में उपाय

सभी के लिए किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण हेल्थकेयर

आयुष्मान भारत

- पीएम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। दो साल से भी कम समय में इस पहल का कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, (1 करोड़ आयुष्मान)। ऐसे रोगी जो महंगी प्रक्रियाएँ नहीं अपना सकते थे और कई वर्षों से सर्जरी स्थगित कर रहे थे, अब इलाज के लिए आगे आने लगे हैं। यह योजना ऐसे रोगियों के लिए आशा की एक उज्ज्वल किरण बनकर आई है।
- 21,000 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया, लगभग 13,412 करोड़ रुपये का इलाज किया गया।
- आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई ने कोविड रोगियों को नि: शुल्क परीक्षण और मुफ्त उपचार प्रदान करने में प्रगति की है। 2,000 से अधिक कोविड 19 रोगी का इलाज किया गया है और 3,000 से अधिक जांच की गई हैं ।
- देश भर में 20,700 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र चालू हो गए हैं।

5 वर्ष से कम उम्र के लिए टीकाकरण / मृत्यु दर कम करना

- अखिल भारतीय स्तर पर रोटावायरस टीकाकरण किया गया है। रोटावायरस टीकाकरण भारत के अस्पताल में 8,72,000 मरीजों, 32,70,000 बाह्यरोगियों की आवक और सालाना 78,000 लोगों की मृत्यु को रोकेगा ।
- ओआरएस को बढ़ावा देने और डायरिया से पीड़ित बच्चों के लिए जिंक के उपयोग के माध्यम से 2022 तक डायरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए , डिफीट डायरिया, नामक एक समर्पित अभियान शुरु किया गया है।

राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम

- 2019-20 में लगभग 1 लाख रोगियों को लाभान्वित करने वाले 12 राज्यों में हेपेटाइटिस सी के लिए मुफ्त उपचार सेवाएं शुरु की गई हैं। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस और राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन भी शुरु की गई है।

वेक्टर जनित रोग

- टीबी जैसे वेक्टर जनित रोगों के उचित प्रबंधन हेतु 655 जिलों में टीबी फ़ोरम स्थापित किये गए ताकि समुदायों में हस्तक्षेप कर इस बीमारी से निपटने के लिए लोगों को और मजबूती से तैयार किया जा सके।
- दवा प्रतिरोधी टीबी रोगियों के उपचार हेतु ओरल ट्रीटमेंट की शुरुआत की गई है। इससे 21.5 लाख टीबी मरीजों में से लगभग 99 प्रतिशत से अधिक रोगियों को अब ओरल ट्रीटमेंट के कारण इंजेक्शन का उपयोग करके होने वाले दर्दनाक प्रक्रिया से बचाया जा सकेगा।

चिकित्सा शिक्षा

- एमबीबीएस की पढ़ाई बठिंडा (पंजाब), रायबरेली (उत्तर प्रदेश), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), बीबीनगर (तेलंगाना), देवगढ़ (झारखंड) और कल्याणी (पश्चिम बंगाल) के एम्स में शुरु की गई है। इसके साथ ही एमबीबीएस की पढ़ाई अब सभी 15 एम्स में होने लगी है। इसके साथ ही देश में नए एम्स की स्थापना हेतु 30,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
- एशपिरेशनल जिलों में 75 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- इस वर्ष मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के सीटों के लिए आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 10 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया गया है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 5000 से अधिक अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें स्वीकृत की गई हैं।
- एमबीबीएस के वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से लागू पाठ्यक्रम में नैतिकता और सॉफ्ट स्किल्स में सुधार पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम

- चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में यह रिफार्म एक गेम चेंजर की भूमिका निभाएगा। यह मेडिकल शिक्षा के छात्रों पर बोझ को कम करेगा, चिकित्सा शिक्षा में संभावनाओं को बढ़ाएगा, चिकित्सा शिक्षा की लागत में कमी लाएगा, प्रक्रियाओं को सरल करेगा, भारत में चिकित्सा सीटों की संख्या को बढ़ाने में मदद करेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेगा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए लोगों तक व्यापक पहुंच प्रदान करेगा।

हेल्थकेयर सर्विस पर्सनल एंड क्लीनिकल इस्टेब्लीसमेंट (हिंसा और संपत्ति को नुकसान) विधेयक, 2019

- हाल ही में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर यह बिल स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा और अस्पताल व क्लीनिक की संपत्ति को नुकसान पहुचाने पर कड़े दंड का प्रावधान करता है।

समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना

जन औषधी सुविधा सेनेटरी नैपकिन

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सस्ती और गुणवत्ता वाले हेल्थकेयर के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु जन औषधी सुविधा सेनेटरी नैपकीन का शुभारंभ किया गया। जिसके तहत 1 रुपये प्रति पैड के हिसाब से सेनेटरी पैड उपलब्ध कराई गई। यह देश की वंचित महिलाओं के लिए स्वच्छ, स्वास्थ और सुविधा 'सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया एक कदम है।
- प्रधानमंत्री के "स्वच्छ भारत - हरित भारत" के सपने को पूरा करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह पैड ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल हैं।
- यह जन औषधी सुविधा नैपकिनस देश भर में 6000 से अधिक पीएमबीजेपी केंद्रों में बिक्री के लिए 11 मई, 2020 तक, इन केंद्रों के माध्यम से 3.44 करोड़ से अधिक पैड अब तक बेचे जा चुके हैं।

महिलाओं के जनन अधिकार की रक्षा

- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2020 महिलाओं के चिकित्सीय, मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच को विस्तारित करता है। पीएम श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के तहत 24 सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति दी।

- महिलाओं के पुनर्प्रजनन अधिकार को प्रोत्साहन देने और उन्हें मानसिक पीड़ा से बचाने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में महिलाओं के कल्याण के लिए ऐतिहासिक विधेयकों को मंजूरी दी जिसके तहत असिस्टेंड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 और सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 लाया गया। जो महिलाओं के रीप्रोडक्टीव राईटस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

पोषण अभियान

- बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक पोषण अभियान व राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना।

- एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत, एनीमिया रोगियों के परीक्षण, उपचार और परामर्श हेतु भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 425 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पोषण अभियान के तहत एनीमिया में तीन प्रतिशत मामलों को कमी लाने में मदद करेगा।

- होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर प्रोग्राम में जहां आशा 15 महीने तक के बच्चों के अतिरिक्त 5 घरों का दौरा करेगी, साथ ही पोषण अभियान के तहत प्रारंभिक चाइल्डहुड डवलपमेंट हेतु काउंसलिंग भी करेंगी। इस पहल के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 217 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

- हर महीने की 9 तारीख को आयोजित इस तिमाही में गर्भवती महिलाओं के लिए 9.64 लाख एंटेनाटल चेक-अप किए गए हैं। सम्मानजनक और गरिमापूर्ण मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए, 317 लेबर रुम और ऑपरेशन थिएटर को (लेबर रुम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव) के तहत सुनिश्चित गुणवत्ता सेवा प्रावधान के लिए प्रमाणित किया गया है।

मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम

- सरकार की नई मातृत्व नीति से महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ा कर 26 सप्ताह की गई है।

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

- मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 तीन तलाक को आपराधिक करार देते हुए मुस्लिम महिलाओं को समाज में बराबरी के अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करता है।
- पीएम श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ की गई एक ऐतिहासिक गलती का सुधार किया गया है और एक "पुरातन और मध्ययुगीन अभ्यास" को इतिहास के कूड़ेदान तक सीमित कर दिया गया है।

सुकन्या समृद्धि योजना

- सुकन्या स्मृद्धि योजना, बालिकाओं के लिए शिक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 21 मई 2020 तक 80,339,993 एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
- यह योजना गरीब परिवारों को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन प्रदान करती है।
- एलपीजी के उपयोग से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ ही आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने में भी मदद मिली है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बाल यौन शोषण के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए पोस्को अधिनियम के अंतर्गत बच्चों पर बढ़ रहे यौन हमले के लिए मौत की सजा और नाबालिगों के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ट्रांसजेंडर लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए लाया गया।
- इसका उद्देश्य इस हाशिए वाले तबके के खिलाफ कलंक, भेदभाव और दुर्व्यवहार को कम करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है।
- कोविड 19 के दौरान सहायता मांगने वाले प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1500 रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से दी गई है। देशभर में लगभग 73 लाख रुपये 4922 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जारी किए गए।
- कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान सामाजिक अलगाव या अन्य कारणों से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा
- मानसिक तनाव और चिंता के मुद्दों पर दैनिक मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए 'कोविड हेल्पलाइन शुरु की गयी।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ऐतिहासिक आरक्षण

- संसद ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान (एक सौ तीन वां संशोधन) 2019 विधेयक पारित किया गया।
- यह गरीबों के उत्थान और सबका साथ, सबका विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की ओर एक ऐतिहासिक कदम है।

अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जनजातियां/ अन्य पिछड़ा वर्ग

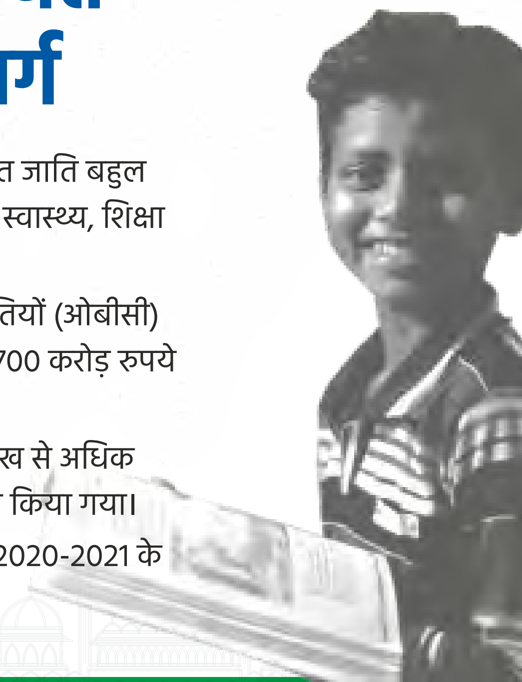

- 2019-20 के दौरान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अनुसूचित जाति बहुल गांवों के एकीकृत विकास के लिए 713 करोड रुपये पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों को जारी किये गये।
- केंद्रीय बजट 2020 में अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण के लिए कुल 1,38,700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- 2019-20 के दौरान विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से 88 लाख से अधिक एससी लाभार्थियों के लिए 3300 करोड़ रुपये से अधिक का आबंटन किया गया।
- एससी छात्रों के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम योजना 2020-2021 के विस्तार के लिए इस योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक वर्ग

- अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया जिससे वर्ष 2018-20 में 35 लाख से अधिक छात्रों ने इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है।
- मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 120 करोड़ रुपये मंजूर किए गए और 2019- 20 के दौरान अल्पसंख्यक संस्थानों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 71 करोड़ रुपये जारी किया गया।।

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान

(शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 से

- संबंधित व्यक्तियों के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में शिक्षण पदों का आरक्षणः (1) अनुसूचित जाति, (2) अनुसूचित जनजाति, (3) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और (4) केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिये किया गया।

जल शक्ति मंत्रालय

- पीएम ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को जो जल संबंधी मामलों का कार्य करते हैं, को एक मंत्रालय के रूप में जोड़ा। जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक सभी भारतीय घरों में पाइप लाइन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की विशाल योजना पर कार्य कर रहा है।
- पीएम श्री नरेन्द्र मोदी ने 2024 तक हर घर में नल का पानी पहुंचाने के लिए जलजीवन मिशन की घोषणा की। इसका मतलब है कि आने वाले पांच वर्षों में 4.5 गुना अधिक घरों को पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुचाया जाएगा जो 72 वर्षों में किया जाना था।